▪ RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 14 ▪ अंक - 20 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » मंगलवार » 11-08-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

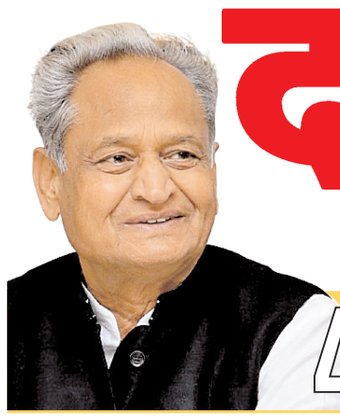

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 गहलोत ने ममता बनर्जी के काफिले पर हमले की निंदा की

6 विदेशी अंशदान कानून पर क्यों मचा है घमासान?

7 कम उम्र में शोहरत, फिर विवादों ने घेरा : हंसिका मोटवानी

फर्स्ट टेक

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप

बोगोटा/एपी। लातिन अमेरिकी देश कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए और लोगों को घबराहट में अपने घरों एवं इमारतों से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा। भूकंप के झटके पड़ोसी इक्वाडोर में भी महसूस किये गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 7.4 होने की जानकारी दी। दोनों एजेंसियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से काफी नीचे था। दोनों ने भूकंप का केंद्र सैन होज़े डेल पाल्मार में बताया, जो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक इलाका है। अधिकारियों ने नुकसान या घायलों की जानकारी तत्काल नहीं दी है।

अमेरिका के शर्तें मानने तक नहीं खुलेगा होर्मुज : ईरान

दुबई/एपी। ईरान ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता, तब तक वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से नहीं खोलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी का जिक्र करते हुए कहा, ''अमेरिका को अपनी गैरकानूनी और विनाशकारी कार्रवाइयां रोकनी होंगी तथा उनकी भरपाई करनी होगी।'' ईरान चाहता है कि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध हटाए और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त करे। होर्मुज जलडमरूमध्य ईंधन आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है। गतिरोध के चलते नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका की राजनीति में ऊर्जा कीमतें बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं।

यूक्रेन के ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत

कीव/एपी। रूस के निजनेकाम्स्क शहर में यूक्रेन की ओर से सोमवार को किए गए ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई और 48 अन्य घायल हो गए। तातारस्तान क्षेत्र के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने किस चीज को निशाना बनाया, लेकिन यह शहर रूस का एक अहम तेल शोधन केंद्र है, जहां दो बड़ी रिफाइनरी और एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र मौजूद हैं। यूक्रेन ने हाल के महीनों में लगभग रोज ही लंबी दूरी के ड्रोन के जरिये रूस के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यह अभियान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर आने और चार साल से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

संसद में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद ने सोमवार को 'कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026' को पारित कर दिया जिसका मकसद विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत ''निश्चितता'' उपलब्ध कराकर अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष खासकर वाम दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस देश में वाम दलों को साहस नहीं है और वे तथ्यों का सामना नहीं कर सकते। वे सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं तथा जवाब सुनना नहीं चाहते...।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों के लिए, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा और कोई शुल्क नहीं लगेगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। विधेयक पर चर्चा एवं पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉक आउट कर गये थे। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान सदस्यों ने जहां इस विधेयक के प्रावधानों से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने और हीरे के प्रसंस्करण उद्योग को मजबूती मिलने की बात कही, वहीं कुछ सदस्यों ने इस विधेयक से यूपीआई के जरिये होने वाले लेनदेन को कर दायरे में लाए जाने की संभावना पर चिंता जतायी।

सदस्यों ने कहा कि आज भारत की बहुत बड़ी आबादी यूपीआई के जरिये लेनदेन कर रही है, ऐसे में उसे कर दायरे में लाने से लोगों और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। विधेयक का उद्देश्य ''विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता'' उपलब्ध कराकर अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस विधेयक में 'फंड मैनेजरों' के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा।

इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों को मिलने वाली कर छूट को 2040-41 तक बढ़ाना भी है, जो किसी भारतीय फैक्टरी को मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराती हैं और वो फैक्टरी अनुबंध विनिर्माण के तहत उनकी ओर से खास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाती है।

दर्शन

पवित्र सावन (श्रावण) माह के दूसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कतारबद्ध श्रद्धालु।

प्रदर्शन

अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर से संबंधित दान की राशि में हेराफेरी या चोरी के आरोपों के विरोध में सोमवार को नई दिल्ली में प्रदर्शन करते साधु, महंत और महामंडलेश्वर्।

मध्यप्रदेश में उफनते नाले में वाहन बहा, नौ लोगों की मौत

राजगढ़ (मप्र)/भाषा। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच 11 यात्रियों को ले जा रहा एक वाहन उफनते नाले को पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया, जिससे एक बालिका समेत नौ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब नौ बजे सारंगपुर कस्बे के पास पदाना बायपास की पुलिया पर हुई। उसने बताया कि चालक नाले में पानी का तेज बहाव होने के बावजूद गाड़ी पार कराने का प्रयास करने लगा तभी वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया।

अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने चालक को आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने वाहन आगे बढ़ा दिया। अधिकारियों के अनुसार तेज बहाव में वाहन के बहने के बाद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सियों की मदद से बचाव अभियान चलाया और दो यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि एक बच्ची समेत नौ लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सारंगपुर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) अरविंद सिंह ने बताया कि सोमवार को भारी बारिश के कारण क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं।

बिरला ने चर्चा के लिए सभी पक्षों से मिलकर रास्ता निकालने की अपील की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए सोमवार को कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और उन पर सार्थक चर्चा के लिए सभी पक्षों को मिलकर रास्ता निकालने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक, कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में बिरला ने सदन की कार्यवाही बाधित रहने पर चिंता जताई और कहा कि सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आपसी सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि गतिरोध समाप्त करने के लिए सभी दलों को मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सदन में वक्तव्य देंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की प्रमुख मांग गृह मंत्री के वक्तव्य को लेकर है और सरकार इसके लिए तैयार है। ऐसे में सदस्यों को सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए और विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखने चाहिए। सूत्रों के अनुसार, बिरला ने सदन में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि सार्थक और रचनात्मक विचार-विमर्श होना चाहिए तथा देश को इस चर्चा को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन के समक्ष कई महत्वपूर्ण जनहित के विषय और विधायी कार्य लंबित हैं। सभी दलों को संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप चर्चा एवं संवाद के माध्यम से सदन को सार्थक और प्रभावी बनाने में सहयोग करना चाहिए।

हम तीनों मांगों पर कायम, गृह मंत्री बताएं कि गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की पेशकश के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि विपक्ष पहले की तरह अपने तीनों मांगों पर कायम है और गृह मंत्री अमित शाह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर ''गोली चलाने'' का आदेश किसने दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विपक्ष की मांग यह नहीं थी कि शाह सदन में आकर किसी भी सामान्य विषय पर बोलें, बल्कि उनसे यह स्पष्ट करने को कहा जा रहा है कि क्या उन्होंने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ संवाददाता सम्मेलन में गांधी ने कहा कि शुरू से ही तीन मांगें की गई थीं। पहली मांग यह कि छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री जवाब दें, दूसरी यह कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके लिए माफी मांगें और तीसरी मांग यह कि राम मंदिर से ''चंदा चोरी'' पर संसद में चर्चा हो। उन्होंने कहा, ''विपक्ष अपनी इन तीनों मांगों पर कायम है और हमें गृह मंत्री की कोरी-काल्पनिक बातों को सुनने का कोई शौक नहीं है।''

केरल का नाम 'केरलम' करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रावधान वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' पेश किया। हालांकि, विधेयक गृह मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध था। विपक्ष के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'केरलम' करने का आग्रह किया गया था।

11-07-2026 सूर्यास्त 6:32 बजे	12-08-2026 सूर्योदय 5:58 बजे

BSE	NSE
78,542.44 (+43.27)	24,583.80 (+13.15)

सोना	चांदी
15,652 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	250,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

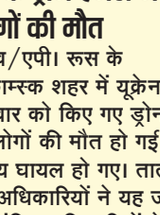

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

विचित्र दौर

कौन सहिष्णु आज यहां है,
सारे ही तो उबल रहे।
अवसरवादी नेता अब भी,
पाले अपने बदल रहे।
सब बस अपनी-अपनी कहने,
बल खा-खा कर मचल रहे।
समझदार तो चुप-चुप बैठे,
टुच्चे-मुच्चे उछल रहे।।

छात्रों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार; गृह मंत्री विस्तार से जवाब देंगे, विपक्ष को सुनना पड़ेगा : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उनका पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न दो बजे शुरू हुई तो रीजीजू ने ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को (छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर) जवाब देना चाहिए।'' रीजीजू ने कहा, ''मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के मामले को लेकर चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं।'' उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा, ''कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा।''

रीजीजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे।

मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा है। यह और अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है। शाह के सदन में नहीं आने के विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से पिछले दिनों कहा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे दिन संसद में रहते हैं। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं तो सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ''यह संसद (मानसून) सत्र का अंतिम सप्ताह है। पिछले तीन सप्ताह पूरी तरह बेकार चले गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार और जवाबदेह है?'' पाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, आप चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। आप मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दें। अब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया है तो आप सदन को व्यवस्थित कीजिए।

> **''यह संसद (मानसून) सत्र का अंतिम सप्ताह है। पिछले तीन सप्ताह पूरी तरह बेकार चले गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार और जवाबदेह है?'' पाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, आप चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। आप मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दें। अब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया है तो आप सदन को व्यवस्थित कीजिए।**

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के नहीं होने पर सुनवाई स्थगित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने वाले वकील के अनुरोध पर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने की अर्जी पर सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए हैं। पीठ ने सवाल किया कि क्या मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

वकील ने कहा, ''हां, वाद संख्या 30-33... कृपया इनपर अगले हफ्ते सुनवाई करें'' पीठ इस अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गई। उच्चतम न्यायालय ने 27 जुलाई को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) किरण एस. की अगुवाई में चार सदस्यों वाली एसआईटी के गठन का संज्ञान लिया। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने के लिए कहा था। पीठ ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) को दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में देरी को लेकर कन्नूर हवाई अड्डे पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कन्नूर/भाषा। कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान का समय बदले जाने और दुबई के लिए एयरलाइन की एक उड़ान को रद्द किए जाने के बाद यात्रियों ने सोमवार सुबह यहां हवाई अड्डे पर प्रदर्शन और हंगामा किया। एयरलाइन से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। टीवी चैनलों पर दिखाए गए दृश्यों में, हवाई अड्डे पर नाराज यात्री एयरलाइन कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए और उन पर उड़ान में देरी या उसे रद्द किए जाने के बारे में पहले से जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते नजर आए। एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि विमान सुबह मस्कट से आने वाला था जिसके आने में देरी हुई क्योंकि तकनीकी कारणों से विमान को मस्कट में ही रोक दिया गया था।

उन्होंने बताया कि यही विमान यहां से तिरुवनंतपुरम रवाना होने वाला था। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा, इसलिए तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ान में देरी हुई। बाद में, मस्कट से विमान पहुंचा है, शीघ्र ही तिरुवनंतपुरम जाने वाली उड़ान रवाना होगी। यात्रियों को देरी के बारे में पहले ही बता दिया गया था। हवाई अड्डा पर नाराजगी जताने वाले लोगों को देरी के बारे में पता था। अधिकारी ने बताया कि तिरुवनंतपुरम जाने वाला विमान सुबह करीब सात बजे उड़ान भरने वाला था। इसमें कई घंटे की देरी हुई।

हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर-शराबे के बीच ही सदन में तीन अन्य विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह की शुरुआत भी पिछले तीन सप्ताह की तरह हंगामेदार रही।

अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग को लेकर कांग्रेस, सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न दो बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को

बिना चर्चा के न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित

तैयार हैं। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा।'' इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इसके बाद, हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं तो सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर आज आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। हंगामा जारी रहने पर, प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने के एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए।

हालांकि, उक्त दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। इस दौरान विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री ''कहां हैं'' कहते सुने गए। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर सदन की बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मानसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन सोमवार को भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके।

प्रधानमंत्री को भेंट किये गए उपहारों की ई-नीलामी से 2025 में 1.89 करोड़ रुपये प्राप्त हुए : शेखावत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किये गए उपहारों और स्मृति चिह्नों की 2025 में ई-नीलामी से सरकार को 1.89 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। शेखावत ने सोमवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस संबंध में आंकड़े साझा किए। उनसे उस रकम की जानकारी मांगी गई थी जो सरकार को पिछले पांच वर्षों में ई-नीलामी से प्राप्त हुई और उन तारीखों के बारे में भी पूछा गया था जब ये नीलामी की गई थीं।

मंत्री द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, सातवें संस्करण (2025) के लिए स्मृति चिह्नों और उपहारों की ई-नीलामी से सरकार को 1.89 करोड़ रुपये मिले, जबकि छठे संस्करण के लिए यह राशि 2.24 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2024 में इसके छठे संस्करण में, 600 से अधिक स्मृति चिह्नों और उपहारों की ई-नीलामी की गई। शेखावत ने 2024 के संस्करण की शुरुआत से ठीक पहले, यहां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संवाददाताओं से कहा था कि यह संग्रह भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास और राजनीति की समृद्ध विविधता को दर्शाता है। मंत्री ने उस समय कहा था कि छठा संस्करण प्रधानमंत्री को भेंट की गई उन स्मृति चिह्नों की सफल नीलामी की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने उस वक्त बताया था कि शुरुआती पांच संस्करणों में इन नीलामियों से 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई। लोकसभा में एक सवाल के तहत शेखावत से यह भी पूछा गया कि 2014 से पहले ऐसी नीलामी कितनी बार की गई थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, 2019 से पहले, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की ओर से स्मृति चिह्नों और उपहारों की कोई नीलामी नहीं की गई थी।

भाजपा ने दुष्कर्म मामले में तेजपाल की दोषसिद्धि पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दुष्कर्म मामले में समाचार पत्रिका 'तहलका' के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की दोषसिद्धि पर कांग्रेस की चुप्पी पर सोमवार को सवाल उठाए। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का तहलका' के साथ लंबे समय से गठजोड़ रहा है।

बंबई उच्च न्यायालय ने तेजपाल (63) को 2013 में गोवा में 'तहलका' की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में एक सहकर्मी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गत बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजपाल को दोषी ठहराए जाने के बावजूद मामले में कांग्रेस की चुप्पी दिखाती है कि अभिव्यक्ति की आजादी और महिलाओं के अधिकारों को लेकर पार्टी का दृष्टिकोण एकतरफा, पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।

त्रिवेदी ने यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह मुद्दा आज इसलिए अहम है, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने दावा किया कि तेजपाल और कांग्रेस के बीच लगभग दो दशक से संबंध हैं। त्रिवेदी ने कहा, ''अगर तेजपाल और कांग्रेस के बीच कोई संबंध नहीं हैं, तो पार्टी कह सकती थी कि टिप्पणी करना या न करना उसका अधिकार है।

बैंकों ने पिछले 12 साल में बड़े कॉरपोरेट को दिए गए 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि बैंकों ने पिछले 12 वित्त वर्षों में बड़े कॉरपोरेट और सेवा क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए 9,95,000 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाल दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2018-19 में बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि 1,48,753 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो 2025-26 में घटकर 20,485 करोड़ रुपये रह गई।

बड़े उद्योगों और सेवाओं पर बकाया ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह वित्त वर्ष 2025 के 63,19,05% करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 69,21,%34 करोड़ रुपये हो गया है। ऋण को बट्टे खाते में डालना लेखा (अकाउंट) संबंधी प्रक्रिया है और इससे कर्जदार (चाहे किसान हो या कॉरपोरेट) को कोई राहत नहीं मिलती। चौधरी ने कहा कि आरबीआई के अनुसार -- वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी 'संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान के दिशानिर्देश 2025' के मुताबिक, कर्ज को बट्टे खाते में डालना (राइट-ऑफ) बैंक द्वारा अपनी बैलेंस-शीट को समायोजित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक लेखांकन प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कर्ज को बट्टे खाते में डालने के बाद भी ऋण प्राप्तकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने हुए हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मंत्री ने एक और प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले पांच साल में डिजिटल भुगतान से जुड़ी 5,85,751 धोखाधड़ी का पता लगाया गया।

घरों के नीचे छिपे खजाने के बहाने लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना में आवासीय परिसर में जमीन के नीचे छिपे खजाने का पता लगाने का झांसा देकर लोगों से लगभग एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कार्य बल) के. एस. राव ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पुलिस टीमों ने घरों के नीचे छिपे खजाने का पता लगाने के बहाने व्यक्तियों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो चौपहिया वाहन, एक ऑटो-रिक्शा, दो मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन, सोने के 25 नकली सिक्के और छह किलोग्राम कोयला सहित अन्य सामान जब्त किया। पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी ने यह दावा किया कि उसे घरों के नीचे छिपे खजाने का पता लगाने का विशेष ज्ञान है। पुलिस ने कहा कि इसके बाद मुख्य आरोपी ने अपने दोस्तों से संपर्क किया और वे सभी आसानी से पैसा कमाने के इरादे से उसके साथ अवैध गतिविधि में शामिल होने के लिए सहमत हो गए।

इंदौर-खण्डवा रेल परियोजना में 1.40 लाख पेड़ों पर चलेगी आरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। मध्यप्रदेश में रेलवे की महू-खंडवा गेज परिवर्तन परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरने वाले एक मार्गखंड में करीब 1.40 लाख पेड़ काटे जाने को केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अंतिम मंजूरी दे दी है और कटाई मॉनसून का मौसम बीतने के बाद शुरू होगी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस अहम परियोजना के तहत रेलवे की ऐतिहासिक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) लाल सुधाकर सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि महू-खंडवा रेल लाइन के गेज परिवर्तन की परियोजना के लिए इंदौर और खरगोन जिलों के वन क्षेत्रों में करीब 1.40 लाख पेड़ काटे जाएंगे। डीएफओ के मुताबिक इनमें इंदौर जिले के लगभग 1.24 लाख पेड़ शामिल हैं।

उन्होंने बताया, ''हमें केंद्र सरकार से पेड़ कटाई की अंतिम अनुमति मिल चुकी है। हालांकि, कटाई का काम मॉनसून का मौसम बीतने पर अक्टूबर से शुरू होगा।'' सिंह ने बताया कि जिस वन क्षेत्र में रेलवे का काम शुरू होगा, उसी क्रम में वहां पेड़ों की कटाई की जाएगी और इसके लिए रेलवे तथा वन विभाग मिलकर योजना तैयार कर रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग ने महू-खंडवा रेल परियोजना के लिए रेलवे पर हरित गलियारा प्रबंधन योजना लागू करने की शर्त भी लगाई है। उन्होंने बताया कि इस शर्त के तहत रेलवे को पटरियों के किनारे स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने होंगे और परियोजना क्षेत्र के भीतर एवं इसके आस-पास उपलब्ध खाली भूमि पर भी पौधरोपण करना होगा। डीएफओ ने बताया कि शर्त के तहत रेलवे को पटरियों के पास वर्षा जल संचयन के ढांचे विकसित करने होंगे व परियोजना के संचालन में ऊर्जा दक्षता के उपाय भी अपनाने होंगे।

एनसीईआरटी का डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा : सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि एनसीईआरटी को दिया गया 'डीम्ड' विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए इसे मजबूत करेगा। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि यह दर्जा केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में एक विचार समूह और एक राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की भूमिका को और मजबूत करेगा। मजूमदार ने कहा कि एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए उसके आवेदन का अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से यूजीसी (डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार किया था।

सूरत मेडिकल कॉलेज में रैगिंग : रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या की, चार वरिष्ठ डॉक्टर निलंबित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सूरत/भाषा। सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के 30 वर्षीय एक रेजिडेंट डॉक्टर ने कथित तौर पर रैगिंग के बाद आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से रातभर जारी जांच के बाद चार वरिष्ठ डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया, जबकि माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख समेत चार संकाय सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मृतक की पहचान हर्ष पांड्या के रूप में हुई है, जो न्यू सिविल अस्पताल से संबद्ध जीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्नातकोत्तर (पीजी) प्रथम वर्ष के छात्र थे। वह रविवार सुबह छात्रावास के कमरे में फंदे से लटके पाए गए।

जीएमसी के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि उनकी मौत की जांच करने वाली रैगिंग रोधी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें भला-बुरा कहा था और अपमानित किया था। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने कहा घटना की वैज्ञानिक तरीकों से गहन जांच की जा रही है और मृतक के पिता, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, को न्याय का भरोसा दिया गया है।

टीसीएस को कर्मचारी डेटा लीक संबंधी साइबर खतरे की चेतावनी मिली

मुंबई/भाषा। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने सोमवार को कहा कि उसे कर्मचारी डेटा के संभावित लीक को लेकर साइबर खतरे की चेतावनी मिली है। इसके साथ ही कंपनी ने स्पष्ट किया कि ग्राहक डेटा, ग्राहक प्रणालियों या उसकी अपनी परिचालन प्रणाली पर किसी तरह के असर का कोई संकेत नहीं है। टीसीएस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, कुछ कर्मचारी सूचनाओं के संभावित खुलासे को लेकर अलर्ट प्राप्त हुए हैं।

आंध्र प्रदेश में दुर्घटना में मेडिकल छात्रा की मौत : पिता ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रा के पिता ने सोमवार को घटना के जिम्मेदार लोगों के लिए मौत की सजा की मांग की। प्रियंका के पिता वेंकटेश ने यहां संवाददाताओं से कहा कि किसी अन्य पिता को अपनी बेटी को खोने का दर्द न सहना पड़े। प्रियंका का शव पोस्टमार्टम के लिए सोमवार को शहर के गांधी सरकारी अस्पताल लाया गया। प्रियंका की नौ अगस्त को यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

प्रियंका (29) को छह अगस्त को आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में एक शॉपिंग मॉल के बाहर गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर नशे में कार चला रहे एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मोटरसाइकिल पर प्रियंका और एक अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रा सवार थी। प्रियंका को पहले राजमहेंद्रवरम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। इलाज के दौरान रविवार दोपहर उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत के बारे में बात करते हुए भावुक हुए वेंकटेश ने कहा कि उनकी बेटी उनकी ''जिंदगी'' थी। तेलंगाना के गडवाल मंडल के रहने वाले वेंकटेश ने बताया कि वह अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए आंध्र प्रदेश के कुरनूल में आकर बस गए थे। तेलंगाना के खेल मंत्री वकिति श्रीहरि और कांग्रेस के पूर्व विधायक एस. ए. ए. संपत कुमार ने गांधी अस्पताल में प्रियंका के माता-पिता को सांत्वना दी। श्रीहरि ने कहा कि तेलंगाना सरकार शोकाकुल परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि संपत कुमार प्रियंका के माता-पिता के साथ उसके शव को तेलंगाना के गडवाल जिले में स्थित उनके पैतृक गांव एक्लासपुर ले गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को प्रियंका की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उसके परिवार के लिए 20 लाख रु. की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

वंदे मातरम् मुद्दे पर केरल सरकार को परेशान कर रही भाजपा : मंत्री जॉन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोझिकोड/भाषा। केरल के परिवहन मंत्री सी. पी. जॉन ने सोमवार को राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के पूर्ण गायन के मुद्दे को लेकर भाजपा पर प्रदेश सरकार को 'परेशान' करने का आरोप लगाया और कहा कि सभी को ऐसी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। जॉन ने कहा कि 'वंदे मातरम' एक सुंदर गीत है, लेकिन इसमें 'भक्ति' या प्रार्थना गीत के तत्व भी हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति गीतों में कुछ भी गलत नहीं है और नास्तिकों समेत कई लोग भी इन्हें पसंद करते हैं लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी विशेष धर्म से जुड़ी बातों का गायन करना उचित नहीं होगा। मंत्री ने कहा, ''हमें भक्ति गीतों से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी विशेष धर्म से जुड़ी बातें गाना गलत है। इसलिए नेहरू (देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू) के समय में राष्ट्रगीत का गायन कुछ चुनिंदा अंतरों तक सीमित रखा गया था।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन भाजपा यह कहकर इस मुद्दे को तूल दे रही है कि इसे पूरा गाया जाना चाहिए और इसके पूर्ण गायन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें इसके प्रति अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। यह मेरा मत है।'' वह छह अगस्त को केरल के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा द्वारा जारी पत्र के संबंध में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे।

प्रस्ताव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय। उन्होंने एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया कि तमिलनाडु के सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संगठनों में कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले 'तमिलथाई वत्थो गीत' गाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर राज्यसभा में द्रमुक और अन्नाद्रमुक सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। राज्यसभा में सोमवार को तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। तमिलनाडु के दोनों इन दलों के बीच यह नोकझोंक कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 पर उच्च सदन में चर्चा के दौरान हुई। चर्चा के दौरान द्रमुक सदस्य पी. विल्सन ने कहा, तमिलनाडु राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि इसकी आबादी कुल आबादी का 6 प्रतिशत है। निवेश के हर 1 रुपये पर हमें केवल 26 पैसे (वापस) मिल रहे हैं...।

उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार मेकेदातु बांध बना रही है और तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 4 मार्च 2026 को एक पत्र लिखकर कर्नाटक सरकार से मेकेदातु बांध का निर्माण नहीं करने का अनुरोध किया था और एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग की थी, जिसका गठन अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब तमिलनाडु के लोग केंद्र सरकार को कर चुका रहे हैं, तो न्यायाधिकरण के गठन में क्या कठिनाई है?

विधेयक का समर्थन करते हुए, अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरै ने कहा, ''मैं वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) से जानना चाहता हूं कि द्रमुक शासन के दौरान, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्टालिन कई वैश्विक कार्यक्रमों में गए, यहां निवेश के लिए कितना पैसा आया जिससे तमिलनाडु को लाभ हुआ।'' थंबीदुरै ने आरोप लगाया कि द्रमुक नीत सरकार के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा और राज्य पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था।

कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने संबंधी याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कावेरी नदी का पानी तत्काल छोड़े जाने के संबंध में कर्नाटक को निर्देश देने संबंधी तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का तमिलनाडु के हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील की दलीलों पर गौर किया। वकील ने कहा कि कम बारिश वाले साल में तमिलनाडु को कावेरी जल में उसका निर्धारित हिस्सा नहीं मिलता है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम इसे बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।'' मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने तीन अगस्त को उच्चतम न्यायालय का रुख कर कर्नाटक सरकार को कावेरी जल में राज्य के हिस्से का पानी तत्काल जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने उसे जितना पानी आवंटित किया था और पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने जितना पानी छोड़ा था वह सीडब्ल्यूआरसी द्वारा आवंटित पानी की मात्रा से बहुत कम था। सीडब्ल्यूआरसी की 28 जुलाई को हुई बैठक में कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिनों तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था; बाद में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने भी इस आदेश को बरकरार रखा।

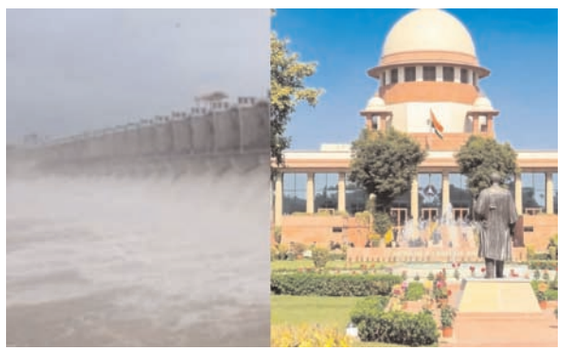

राज्य सरकार ने कहा कि 29 जुलाई से दो अगस्त के बीच बिलिगुंडलू में छोड़े गए पानी की मात्रा 158 से 550 क्यूसेक के बीच थी। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि तीन अगस्त तक कर्नाटक के जलाशयों कृष्णराज सागर (केआरएस), कबिनी, हरंगी और हेमावती में कुल 77.537 टीएमसी जल भंडार था और कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का पानी तय अनुपात में छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल में कर्नाटक के केआरएस और कबिनी बांधों के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद बिलिगुंडलू में मिलने वाला पानी 26.954 टीएमसी होना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हाल में कर्नाटक के केआरएस और कबिनी बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद बिलीगुंडलु में आनुपातिक मात्रा 26.954 टीएमसी होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि इसके अनुसार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 4.536 टीएमसी पानी की मात्रा काफी कम है। तमिलनाडु सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी देने में ''विफल'' रहा है और 26.954 टीएमसी पानी उसने तमिलनाडु को नहीं छोड़ा है। इससे पहले, तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने भी उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। पार्टी ने न्यायालय से कर्नाटक सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वह राज्य को कावेरी नदी जल का उसका हिस्सा तुरंत जारी करे। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक को उच्चतम न्यायालय के 2018 के अंतिम फैसले का सख्ती से पालन करना चाहिए और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों को मानना चाहिए।

'जेन जी के लिए सेना में शामिल होने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए'

कोयंबटूर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने सोमवार को कहा कि आज के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अन्नामलाई ने यहां मेजर मदन कुमार की किताब के विमोचन कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने अपनी बात युवाओं के उस वर्ग के सामने रखी, जिसे आमतौर पर 'जेन जी' कहा जाता है। हाल ही में 'वी द लीडर्स' नामक संगठन स्थापित करने वाले अन्नामलाई ने कहा कि आज की पीढ़ी जीवन में किसी उद्देश्य की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा, जेन जी के रूप में, आपको एक बड़े उद्देश्य की जरूरत है; आज आप जीवन में एक बड़े उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। अन्नामलाई ने कहा, अगर आप किसी उद्देश्य की तलाश में हैं, तो वर्दी आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जेन-जी अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको सैन्य सेवा को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखना चाहिए।

ग्राफिक इंडिया और सद्गुरु ने एनिमेशन फिल्म शिव : 'द आदियोगी' के लिए हाथ मिलाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/कोयम्बटूर। 'एनिमेशन स्टूडियो ग्राफिक इंडिया' ने भगवान शिव पर आधारित एनिमेशन फीचर फिल्म 'शिव : द आदियोगी' के निर्माण के लिए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु से हाथ मिलाया है।

'ग्राफिक इंडिया' को पौराणिक कथाओं पर आधारित एनिमेशन वेब सीरीज 'द लेजेंड ऑफ हनुमान' के निर्माण के लिए जाना जाता है। इस संबंध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 'शिव : द आदियोगी' की कहानी सद्गुरु और ग्राफिक इंडिया' के सह-संस्थापक शरद देवराजन ने लिखी है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह फीचर फिल्म शिव को 'आदियोगी' यानी प्रथम योगी के रूप में पेश करेगी और उन परिस्थितियों को दिखाएगी, जिनके कारण उन्होंने अपना ज्ञान मानवता के साथ साझा किया।

विज्ञप्ति में कहा गया कि 'शिव : द आदियोगी' प्रेम, विरह, क्रोध और आत्मबोध जैसे विषयों के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें सृष्टि के निर्माण से पहले के अंधकार से लेकर कैलाश के शिखर तक का सफर दर्शाया जाएगा।

'सिंगाप्पेन मैराथन 2026' में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास सेंट्रल ने इनरव्हील क्लब्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट 323 और सिंगाप्पेन स्पेशल फोर्स (एसएसएफ) के सहयोग से 'सिंगाप्पेन मैराथन' का आयोजन किया। यह एक सर्व-महिला दौड़ थी, जिसका उद्देश्य शुरुआती टीकाकरण के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) की रोकथाम के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और सिंगाप्पेन स्पेशल फोर्स एवं 1091 हेल्पलाइन के ज़रिए महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था।

यह आयोजन 9 अगस्त को सुबह 6 बजे आइलैंड ग्राउंड्स, चेन्नई से शुरू हुआ। कॉलेज छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, गृहणियों और नवनिर्मित सिंगाप्पेन स्पेशल फोर्स के एक समर्पित दल सहित लगभग सैकड़ों प्रतिभागियों ने आइलैंड ग्राउंड्स से ऐतिहासिक लाइटहाउस तक और वापसी का 8 किलोमीटर का मार्ग पूरा किया। मैराथन को मुख्य अतिथि के. भावनेश्वरी, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), सिंगाप्पेन स्पेशल फोर्स, तमिलनाडु सरकार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

दिल्ली पुलिस ने जालसाजी मामले में 12 साल से फरार आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जालसाजी के एक मामले में 12 साल से फरार 62 वर्षीय एक व्यक्ति को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है जहां उसने पोल्ट्री व्यवसायी के रूप में एक नया जीवन शुरू कर लिया था। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा ने इस मामले को हाल में अपने हाथ में लिया था और उसके मोबाइल नंबर की निगरानी शुरू कर दी थी। यह मामला राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों के नाम पर जारी फर्जी लैटरहैड से जुड़ा है।

पुलिस ने कहा कि 50,000 रुपये के इनामी मनोहरन कंधासामी को चार अगस्त को नामक्कल जिले के तिरुचेंगोडे के बाहरी इलाके में एक गोदाम से गिरफ्तार किया गया।

अपराध शाखा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, कंधासामी को 2014 में भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था, जब उसने कथित तौर पर राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों के फर्जी लैटरहेड से जुड़े जालसाजी मामले में अदालत के सामने पेश होना बंद कर दिया था।

पुलिस के अनुसार, यह मामला 2007 का है जब हैदराबाद के 65 वर्षीय एक व्यक्ति ने दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में शिकायत की कि एक धर्मशाला में अलमारी में रखे सोने के गहने और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया है। जांच के दौरान पुलिस ने कंधासामी को पकड़ लिया।

हालांकि चोरी का माल बरामद नहीं हुआ लेकिन पुलिस को उसके कब्जे से कई मुद्रित और खाली लैटरहैड मिले जो कथित तौर पर राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों से संबंधित थे।

अधिकारी ने कहा, दस्तावेज़ बाद में फर्जी पाए गए, जिसके बाद 2008 में एक अलग मामला दर्ज किया गया। बाद में मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। कंधासामी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन लगभग एक महीने बाद उसे जमानत मिल गई। इसके बाद उसने अदालत में पेश होना बंद कर दिया और भूमिगत हो गया। शहर की एक अदालत ने 2014 में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई।

पुलिस ने बताया कि हाल में एक टीम ने इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का विश्लेषण किया और एक मोबाइल नंबर की पहचान की जिसे कंधासामी तमिलनाडु में सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा था। पुलिस ने कहा कि एक महीने से अधिक समय तक तकनीकी निगरानी और सत्यापन के बाद, टीम ने तिरुचेंगोडे में उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान कंधासामी ने पुलिस को बताया कि वह जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था क्योंकि उसे दोषसिद्धि और कारावास का डर था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने अपना निवास स्थान बदल लिया, अपने पिछले सहयोगियों से संपर्क तोड़ दिया और तमिलनाडु चला गया, जहां वह अपने परिवार के साथ बस गया और पोल्ट्री व्यवसाय करने लगा। उन्होंने बताया कि मूल रूप से कर्नाटक के मंगलुरु का रहने वाला कंधासामी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।

शिवकुमार ने कर्नाटक में विभागों के बंटवारे पर वेणुगोपाल से की चर्चा

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से राज्य मंत्रिमंडल में फिर से मामूली फेरबदल करने और हाल में शामिल किए गए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा की। डी के ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दो घंटे से अधिक समय तक बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने सोमवार सुबह वेणुगोपाल से बातचीत की और फिर बेंगलूरु के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य को शामिल करने के साथ-साथ नये मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाने पर चर्चा की। नाराज विधायकों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रियों के विभागों में मामूली फेरबदल भी किए जाने की संभावना है तथा हाल में शामिल किए एक या दो मंत्रियों को हटाया जा सकता है। शिवकुमार ने खरगे से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा था, ''हमें एक महिला को शामिल करना है और हम ऐसा करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है।''

बिड़दी परियोजना : देवेगौड़ा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जद(एस) के मार्च में शामिल हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के बेंगलूरु दक्षिणी जिले के बिड़दी में जीबीआईटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जनता दल (सेक्युलर) की ओर से आयोजित पदयात्रा में सोमवार को पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा शामिल हुए।

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसानों की आजीविका को बर्बाद करने की कोशिशें जारी रहीं, तो वह और उनकी पार्टी इसका विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में घटक जद(एस) की युवा शाखा के अध्यक्ष और देवेगौड़ा के पोते निखिल कुमारस्वामी की अगुवाई में बिड़दी के पास बायरामंगला से बेंगलूरु शहर के फ्रीडम पार्क तक तीन दिवसीय पदयात्रा कर रही है और सोमवार को पदयात्रा का दूसरा दिन है। रविवार को बायरामंगला में जद(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक के साथ मिलकर तीन दिवसीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस यात्रा में कुल मिलाकर लगभग 38 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।

बिड़दी के बीजीएस सर्कल में मार्च के दूसरे दिन की शुरुआत के समय 93 वर्षीय देवेगौड़ा ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नम्मा भूमि, नम्मा हक्कू' (हमारी ज़मीन, हमारा अधिकार) जैसे नारे लगाए और सरकार पर आरोप लगाया कि वह रियल एस्टेट के हितों को बढ़ावा दे रही है और किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। देवेगौड़ा ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह, अपने बेटे कुमारस्वामी, पोते निखिल, जद(एस) के नेताओं और विधायकों के साथ मिलकर किसानों और आम लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ''आज वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री झूठा आरोप लगा रहे हैं कि देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और निखिल यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके अलावा कोई और वोक्कालिगा मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, अगर वह अच्छा काम करता है, तो हम उसका समर्थन करेंगे।'' मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने दावा किया था कि वह जीबीआईटी परियोजना को केवल आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी शुरुआत कुमारस्वामी ने 2006 में मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। देवेगौड़ा ने मुख्यमंत्री के दावे पर पलटवार करते हुए कहा, ''शिवकुमार, आप दो साल तक राज्य पर राज करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसानों की आजीविका खत्म करने के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं?'' उन्होंने सवाल किया, ''आप किसानों की आजीविका खत्म करके यह परियोजना लागू कर रहे हैं। किसके लिए? कृपया सच बताइएं - किसके लिए?''

देवेगौड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक, बेंगलूरु विकास प्राधिकरण (बीडीए)के तहत 20,000 स्थल खाली हैं। इतना ही नहीं, बेंगलूरु की अलग-अलग परियोजनाओं में भी कई भूखंड खाली हैं। उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है और बड़ी संख्या में बने-बनाए घर भी खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बनाई गई समिति को इस बारे में आंकड़े एकत्र करने चाहिए। उन्होंने कहा, ''आप (शिवकुमार) राज्य पर शासन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक आप किसानों की आजीविका को खत्म करने की कोशिशें बंद नहीं करते, तब तक यह देवेगौड़ा जो भले 93 साल का है, किसी भी वजह से पीछे नहीं हटेगा, और यही बात कुमारस्वामी और निखिल पर भी लागू होती है। इसे लिख लीजिए। हम किसानों की आजीविका को बर्बाद करके आपको अपनी इमारतें नहीं बनाने देंगे।'' देवेगौड़ा ने कहा कि उन्हें पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है कि सिद्दरामय्या को हटाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवकुमार ने दिल्ली में क्या आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, ''उन वादों को पूरा करने के लिए, आप यहां के किसानों की ज़मीनें देकर उनकी आजीविका बर्बाद कर रहे हैं। आप यह ज़मीन किसे देना चाहते हैं? किस कंपनी को? सच बताइए।'' पूर्व प्रधानमंत्री ने आगाह करते हुए कहा कि किसी को भी उन्हें बूढ़ा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''मेरा शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन मेरी बुद्धि नहीं। मेरी बुद्धि अब भी ठीक है। मुझे लोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा।'' उन्होंने लोगों से 19 अगस्त को बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।

कांग्रेस की 'हिसाब मांगो रैली' पर पुलिस ने पानी की बौछार की , महिला कार्यकर्ता बेहोश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर में सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नगर निगम मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की जिससे एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई। कांग्रेस ने टोंक रोड पर नेहरू पैलेस से नगर निगम मुख्यालय तक 'हिसाब मांगो रैली' निकाली। पार्टी ने जयपुर में घर-घर कचरा संग्रहण में कथित अनियमितताओं और खराब सफाई व्यवस्था, जलभराव, सीवर लाइनें जाम होने, क्षतिग्रस्त सड़कों और खराब पड़ी 'स्ट्रीट लाइट' एवं अन्य नागरिक समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों के नगर निगम मुख्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैरिकेड पर चढ़ गए और जयपुर की बदहाल नागरिक व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

खाचरियावास ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है तथा हाल में हुई बारिश के बाद शहर की स्थिति और खराब हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शहर की सफाई और जलभराव की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस अपना आंदोलन और तेज करेगी। उन्होंने कहा, पुलिस तैनात की जा सकती है और बैरिकेड लगाए जा सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक जारी रहेगी। प्रदर्शन में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

चोरी के डर से खेत में दबाए पांच लाख, दीमक ने नोटों को किया बर्बाद

जोधपुर। राजस्थान के बालोतरा जिले में एक किसान कथित तौर पर खेत में पांच लाख रुपये नकद मिट्टी के नीचे दबाकर भूल गया कि उसने ये पैसे कहां छिपाये हैं लेकिन अब उसे बुवाई के दौरान ये पैसे मिल गये हैं। हालांकि किसान का कहना है कि ये पैसे दीमक लगने से खराब हो गए हैं। पचपदरा के मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि उसने जमीन बेचकर मिले पांच लाख रुपये से नेवई गांव में अपने कृषि क्षेत्र में एक कमरा बनवाने की योजना बनाई थी। किसान ने बताया कि चोरी होने या परिवार के सदस्यों द्वारा रकम खर्च किए जाने के डर से उसने पांच लाख रुपये पॉलीथिन की थैली में रखे तथा अपनी पत्नी एवं बेटों को बताए बिना खेत में एक गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। किसान का कहना है कि बाद में उसे वह जगह ठीक से याद नहीं रही, जहां उसने रुपये दबाए थे। इसके बाद उसने करीब 10 बीघा क्षेत्र में कई दिनों तक रकम की तलाश की, लेकिन उसे रुपये नहीं मिले।

इसके बाद मेघवाल ने अपनी पत्नी और बेटों को खेत में रुपये दबाने की जानकारी दी। परिवार के सदस्यों ने भी काफी तलाश की, लेकिन रकम नहीं मिली और अंततः उन्होंने तलाश बंद कर दी। हाल में हुई बारिश के बाद परिवार ने खेत में बुवाई की तैयारी शुरू की। शुक्रवार को ट्रैक्टर से खेत की जुताई के दौरान जमीन में दबाई गई पॉलीथिन की थैली बाहर निकल आई। परिवार को उसमें रुपये मिले, लेकिन तब तक नोट काफी खराब हो चुके थे।

गहलोत ने ममता बनर्जी के काफिले पर हमले की निंदा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने रविवार को उत्तर 24 परगना में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर कथित हमले की निंदा की और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राज्य में ''अराजकता और भय'' का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहीं बनर्जी के वाहन पर पत्थर, कीचड़ और जूते फेंके गए तथा पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी की गई। गहलोत ने एक बयान में कहा,भाजपा के शासन ने अराजकता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। उत्तर 24 परगना में आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर हुआ हमला बदले की राजनीति के सबसे घृणित रूप का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बनर्जी ने स्वयं बताया है कि यदि उनके वाहन की खिड़कियां खुली होतीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस की मौजूदगी में भी सुरक्षित नहीं है, तो राज्य में विपक्ष के आम कार्यकर्ताओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि यह घटना केवल किसी नेता पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को डराने और दबाने का प्रयास है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और प्रेम तथा सद्भाव की बात करते हैं, जो देश की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा, फिर भी भाजपा इसे समझने को तैयार नहीं दिख रही है। गहलोत ने कहा कि पुलिस की कथित मौजूदगी में हमला होना प्रशासन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना का तत्काल संज्ञान लेने, बनर्जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

खरीद प्रक्रिया में अधिकतम राजीविका उत्पादों को किया जाए शामिल : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजीविका के उत्पादों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि हो पाए। श्रीनिवास सोमवार को शासन सचिवालय में राजकीय विभागों की खरीद प्रक्रिया में राजीविका के उत्पादों को प्राथमिकता देने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि बाजार की मांग के अनुरूप राजीविका के उत्पादों की उचित मैपिंग की जाए। साथ ही इन उत्पादों की बिक्री एवं बाजार विस्तार के लिए मार्केट रिसर्च, उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, प्रबंधन, लॉजिस्टिक एवं तकनीकी सहयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राजीविका के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों को उनके दैनिक कार्यों में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खरीद में राजीविका के उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पाद, सैनिटरी नेपकिन, कपड़े, थैले, उपहार सामग्री, फूल, कार्यालय स्टेशनरी सहित अन्य उपयोगी वस्तुओं को खरीदते समय स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से राजीविका के उत्पादों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ राजकीय विभागों में भी उचित अवसर प्राप्त होंगे। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल एवं उद्यमिता विभाग संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कुंजी लाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिनेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राजेश कुमार यादव सहित सबंधी विभागों के प्रमुख सचिव, शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन, बान और शान : जोगाराम पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में कलेक्ट्रेट परिसर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला स्तरीय ई - बाइक तिरंगा रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर नई सड़क, भाटी चौराहा रातानाडा, सर्किट हाऊस होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान शहरवासियों ने कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर रैली का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

पटेल ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश आन, बान, शान और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ की गई तिरंगा यात्रा जन-जन के अभियान के रूप में नई पीढ़ी में राष्ट्र भावना को सशक्त करने का माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा प्रत्येक भारतीय के दिल में बसता है, इसके सम्मान एवं गौरव की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा मां भारती के प्रति कर्तव्य निभाना किसी पूजा से कम नहीं है और उसी भाव से हम सब मातृभूमि के कल्याण के लिए निरंतर परिश्रम करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान अवश्य दें। उन्होंने कहा हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है। उन्होंने कहा इस तिरंगे की आन-बान को कायम रखने के लिए प्रत्येक भारतवासी कृत- संकल्पित है। उन्होंने कहा हमारी आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदान को युगों-युगों तक याद रखने के लिए यह तिरंगा हर घर में फहराया जाना चाहिए।

पूर्व सांसद राजेन्द्र गहलोत ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। हर घर लहराता हुआ तिरंगा राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है। लेकिन यह सम्मान हमारे घरों के साथ ही हमारे दिलों में भी होना चाहिए।

जिला स्तरीय 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आयोजित ई-बाइक तिरंगा रैली के अवसर पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्मिकों एवं प्रतिभागियों को राष्ट्रध्वज के सम्मान एवं देश की एकता-अखंडता की शपथ दिलाई। इसके पश्चात उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ई- बाइक रैली को जिला कलक्टर कार्यालय से रवाना किया।

ई - बाइक रैली में सीमा सुरक्षा बल के जवानों, राजस्थान पुलिस की कालिका बटालियन, सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, स्काउट के विद्यार्थियों, पुलिस कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, नगर निगम, जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।

एक राज्य-एक चुनाव से आर्थिक बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव : सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर।राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सोमवार को शासन सचिवालय में आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में चुनाव प्रक्रिया के सुचारू, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

राजेश्वर सिंह ने कहा कि एक राज्य-एक चुनाव के तहत सभी पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने का निर्णय लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता,प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता तथा चुनाव के दौरान पारदर्शिता बनाए रखना है। एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, जिससे विकास योजनाओं की गति में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि समयबद्ध चुनाव कराने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं।

राजेश्वर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने,आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ समन्वय कर व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही,नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने,संवीक्षा एवं नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जुलाई, 2026 को जारी आदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव के संदर्भ में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।

बैठक में नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की चरणबद्ध व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राजेश वर्मा ने बताया कि 39 जिलों में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में तथा दो जिलों फलोदी एवं सलूम्बर में एक चरण में कराए जाएंगे।

इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 36 जिलों में चार चरणों, 4 जिलों में दो चरणों तथा एक जिले में एक चरण में चुनाव कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जैसलमेर जिले में एक चरण के अनुसार चुनाव की व्यवस्था है। बैठक के दौरान वर्मा ने बताया कि प्रथम चरण में 140 नगर निकायों, 5,050 वार्डों एवं 10,185 मतदान केन्द्रों के लिए 71,295 सिविल निर्वाचन टीम एवं 61,110 पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता होगी, जबकि द्वितीय चरण में 169 नगर निकाय, 5,195 वार्ड एवं 6,280 मतदान केन्द्रों के लिए 43,960 सिविल निर्वाचन टीम तथा 37,680 पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता होगी। वर्मा ने बताया कि निर्वाचन में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं नगर निकाय सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा।

राजस्थान में बारिश सामान्य से 12.46 फीसदी कम

जयपुर। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि सीकर और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में सीकर के नीमकाथाना में सर्वाधिक 85 मिलीमीटर बारिश हुई, जो भारी बारिश की श्रेणी में आता है।

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में एक जून से 10 अगस्त तक कुल 234.02 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य औसत बारिश 267.34 मिलीमीटर है। इस तरह राज्य में बारिश 12.46 प्रतिशत कम रही। हालांकि, राज्य में बारिश सामान्य श्रेणी में है। सामान्य बारिश की श्रेणी औसत से 19 प्रतिशत कम से लेकर 19 प्रतिशत अधिक तक मानी जाती है।

मौसम विभाग ने बताया कि बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, डीग, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं और फलोदी में औसत से 20 से 59 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है जबकि अजमेर, अलवर, बालोतरा, चूरू, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, प्रतापगढ़, सलूंबर और सीकर सामान्य वर्षा हुई।

कृषि सेवाओं को पारदर्शी एवं किसान केन्द्रित बनाया जाए : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को एग्रीस्टैक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एग्रीस्टैक के तहत फॉर्मर रजिस्ट्री, फॉर्मर आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे के साथ डेटा सिंक्रोनाइजेशन, एग्रीस्टैक आधारित उर्वरक वितरण, एमएसपी पर खरीद तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टैक का उद्देश्य डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के साथ कृषक को उसकी भूमि, फसल एवं कृषि सेवाओं से संबंधित सुविधाएं एकीकृत एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ एग्रीस्टैक के सभी निर्धारित माइलस्टोन समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष कृषकों के पंजीकरण को अभियान के रूप में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों में विशेष फील्ड विजिट, संभागवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं प्रशिक्षण तथा कृषि पर्यवेक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के साथ इसे निरंतर अद्यतन रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मोबाइल ऐप का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा शेष कृषकों को एसएमएस, समाचार पत्रों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए।

श्रद्धा

पवित्र सावन महीने में सोमवार को अजमेर के ग्रामीण इलाके में पुष्कर झील से पवित्र जल भरकर लौटतीं महिला श्रद्धालु।

झारखंड पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ीं, आंसू गैस के गोले दागे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अवरोधक तोड़े और राज्य विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनपर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

इस बीच, आज दोपहर विधानसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में वे घायल हो गए। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब प्रदर्शनकारी नए विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर जगन्नाथपुर मंदिर के पास अंतिम अवरोधक तक पहुंचे थे। वर्तमान में झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। पीयूष कुमार सोनी नामक एक प्रदर्शनकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, लाठीचार्ज बहुत बर्बर था। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हम पर लाठियां बरसाईं। ये सिर्फ हमें शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं हमारी सोच को नहीं दबा सकते। उन्होंने दावा किया, कई छात्राओं को भी चोटें आईं। पुलिस ने हमारे सिर, हाथों, चेहरे हर जगह वार किये। हजारीबाग जिले से आए विक्रम कुमार ने दावा किया कि उनके सिर पर चोट आई है। उन्होंने कहा, ''हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार हमारे साथ जो कुछ भी कर रही है वह ठीक नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे फिर आपकी पुलिस हम पर लाठियां क्यों बरसा रही थी।''

सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन है और इसी दिन प्रदर्शनकारियों ने पुराने विधानसभा भवन के बाहर से सुबह करीब साढ़े 10 बजे मार्च शुरू किया। छात्रों ने प्रदर्शन के 17वें दिन अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य इकाई के अध्यक्ष शशांक राज ने कहा, ''आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है, क्योंकि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाईं। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।'' उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों की मांगों के प्रति ''संवेदनहीन'' नहीं होने की अपील की। इस मुद्दे पर नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) नेता देवेंद्रनाथ महतो एंबुलेंस में बैठकर इस मार्च में शामिल हुए। इस दौरान वह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए नजर आए। विधानसभा तक मार्च के रास्ते पर कंटीले तारों के अवरोधक लगाए जाने का विरोध करते हुए महतो ने कहा कि छात्रों के साथ हुए अन्याय को लेकर उनमें गुस्सा पनप रहा है। उन्होंने कहा, ''सरकार हमारी आवाज दबाने पर आमादा है। अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे।'' प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिये हुए थे, जिस पर लिखा था ''जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करें या सीबीआई जांच कराएं'', ''जेएसएससी पर छापेमारी करने से क्यों बच रही है सीआईडी?'' और ''निष्पक्ष जांच कराएं, सच सामने लाएं''।

लक्ष्मी योजना दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी योजना : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली/भाषा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि लक्ष्मी योजना, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता योजना है। योजना के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य 17 लाख लाभार्थियों का है और जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया नहीं रुकेगी।

गुप्ता ने कहा, ''दिल्ली लक्ष्मी योजना सरकार की सबसे बड़ी योजना है, चाहे 15 साल की सरकार (कांग्रेस) हो या 11 साल की सरकार (आप'), किसी ने यह नहीं किया। (भाजपा) सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के लिए ऐसा करने का संकल्प लिया है।'' उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने के केवल 10 दिन में इसके तहत लगभग 5.92 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य 17 लाख ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, जो वास्तव में हकदार हैं। जब तक हम उस आंकड़े तक नहीं पहुंच जाते तब तक पंजीकरण बंद नहीं करेंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना एक अगस्त को शुरू की गई थी। योजना की पहली किस्त रक्षा बंधन के त्योहार के आसपास जारी होने की संभावना है, जो 28 अगस्त को मनाया जाएगा।

राहुल ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा की

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा कि वह एवं उनकी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में गांधी ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ हिंसा की निंदा करती है, चाहे ऐसी घटना कहीं भी हुई हो। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, झारखंड के छात्रों के लिए मुझे यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हैं। यह मायने नहीं रखता कि यह कहां हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसकी (हिंसा) सलाह नहीं देते, हम इसका समर्थन नहीं करते। हमें इसको लेकर कोई असमंजस नहीं है।'' गांधी ने कहा, ''जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है तब हम उसे हिंसा का प्रयोग करने के खिलाफ हैं।'' प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अवरोधक तोड़े और राज्य विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनपर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच, आज दोपहर विधानसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में वे घायल हो गए। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब प्रदर्शनकारी नए विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर जगन्नाथपुर मंदिर के पास अंतिम अवरोधक तक पहुंचे थे। वर्तमान में झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है।

बैंक संबंधी नए कानून से अदालत में मान्य होंगे डिजिटल-इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि बैंकों के बही साक्ष्य संबंधी प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद बैंकों के लेनदेन संबंधी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की प्रमाणित प्रति अदालत में मान्य हो सकेगी। उच्च सदन में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026' पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में कारोबार की सुविधा के लिए कई औपनिवेशिक कानूनों को हटाया गया और कई में बदलाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटीलकरण हो गया है और बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेनदेन को लेकर कागजी रिकार्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और मूल कानून में डिजिटल रिकार्ड का उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की प्रमाणिक प्रति को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकेगा और उसे मान्यता मिलेगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अदालत में बैंक लेनदेन से संबंधित रिकार्ड पेश करते समय गोपनीयता को पूरी तरह से बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल स्वरूप या भौतिक स्वरूप, किसी भी तरह से रिकार्ड को पेश किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित कानून में 'बैंककार बही' की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल, क्लाउड-आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एकसमान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार-बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए 'विशेष कारण' (स्पेशल कॉज) परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

उत्तर कर्नाटक तेरापंथ आंचलिक सभा का शपथ ग्रहण समारोह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बल्ली। शहर के तेरापंथ भवन में चातुर्मासार्थ विराजित डॉ. मुनि आलोक कुमार जी के सान्निध्य में जैन श्वेताम्बर उत्तर कर्नाटक तेरापंथ आंचलिक सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेन्द्र पालगोता एवं उनकी नई कार्यकारिणी समिति ने शपथ ग्रहण की। पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र जीरावला व अन्य वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थित में शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष के रूप में महेन्द्र पालगोता, उपाध्यक्ष मांगीलाल तातेड़ एवं राजेश सुराणा ने, महामंत्री पुष्पराज बाफना, कोषाध्यक्ष प्रमोद चौपड़ा, सहमंत्री केसरीचन्द गोलछा एवं किशोर तलेसरा, संगठन मंत्री(4) प्रवीण गोठी, महावीर नाहर, जगदीश कोठारी व प्रवीण आंचलिया तथा प्रचार प्रसार मंत्री देवराज चौपड़ा सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। समारोह में उपस्थित उत्तर कर्नाटक तेरापंथ आंचलिक सभा, गदग व महासभा के प्रतिनिधियों व सदस्यों ने नई कमेटी को शुभकामनाएं दी।

मुनिश्री आलोक कुमारजी ने गुरु-निष्ठा, संघ सेवा, समाज सेवा, प्रमाणिकता एवं कर्तव्यनिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए नवगठित कार्यकारिणी समिति को आशीर्वाद प्रदान किया और समाज एवं संघ की सेवा में निरंतर अग्रसर रहने की लिए प्रोत्साहित किया। सुरेश कोठारी एवं पूर्व मंत्री रमेश चोपड़ा ने विभिन्न सत्रों का संचालन किया। मंत्री पुष्पराज बाफना ने धन्यवाद दिया।

अपनी 105 साल की मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर संभल लौटा बेटा-पोता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संभल (उप्र)/भाषा। सावन माह में लाखों कांवड़िये जहां भक्ति और श्रद्धा के साथ गंगाजल लेकर आ रहे हैं, वहीं संभल के एक शिवभक्त ने अपनी कांवड़ को मातृसेवा का रूप देकर सबको भावुक कर दिया। चंदौसी तहसील के खेतापुर गांव के जोगिंदर (52) ने अपने बेटे प्रमोद (26) के साथ 105 वर्षीय मां हरदेई को हरिद्वार से कांवड़ में बैठाकर करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर सोमवार को घर लौटे। जोगिंदर के कंधों पर कांवड़ के एक पलड़े में 28 लीटर गंगाजल था तो दूसरे पलड़े में साक्षात उनकी मां बैठी थीं। जहां-जहां से यह अनोखी कांवड़ गुजरी, लोगों ने नमन किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस प्रयास की खूब सराहना की। जैसे ही जोगिंदर अपनी कांवड़ के साथ संभल पहुंचे, सड़क किनारे श्रद्धालुओं और राहगीरों की भीड़ जुट गई। पूरे रास्ते लोग उनकी मातृभक्ति और शिवभक्ति की प्रशंसा करते रहे।

जोगिंदर ने बताया, ''मेरा सपना था कि अपनी 105 वर्षीय मां को हरिद्वार में गंगा स्नान कराऊं। इसलिए अपने बेटे के साथ हरिद्वार गया और वहां से कांवड़ के एक पलड़े में गंगाजल और दूसरे में मां को बैठाकर पैदल लौट आया।'' उन्होंने बताया कि वे 28 जुलाई को हरिद्वार से चले थे और नौ दिन बाद आज संभल पहुंचे हैं तथा अब मंगलवार को शिव तेरस पर वे अपनी मां के साथ गंगाजल से भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। जोगिंदर के पुत्र प्रमोद ने कहा, हमारा और पिताजी का सपना था कि दादी को एक बार गंगा स्नान कराकर लाएं। इस बार मौका मिला तो पूरा कर दिया। हरिद्वार से यहां तक आने में नौ दिन लगे। इस कांवड़ का वजन करीब 65 किलो है, जिसमें 28 लीटर गंगाजल है। यह आस्था थी तो ले आए, सपना पूरा हो गया। हरदेई ने कहा, ''मेरे बेटे और पोते ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे बहुत खुशी है।'' यह कहते हुए वह भावुक हो गईं।

स्व इन्द्रियों पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य : कमलेशमुनि

मैसूरु/दक्षिण भारत। शहर के स्थाकवासी जैन संघ हब्लदकेरी के तत्वावधान में स्थानक भवन में चातुर्मासार्थ विराजित संतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने उपाध्याय केवल मुनिजी की जयंती पर संतश्री के गुणों को याद करते हुए कहा कि दुश्मनों पर विजय पाना आसान है परंतु अपनी इन्द्रियों पर विजय पाना अत्यंत कठिन है।

इन्द्रियों का गुलाम बना हुआ व्यक्ति मकड़ी के जाले की भाँति उलझकर अपने प्राणों का अंत कर देता है। इन्द्रियों का गुलाम आत्मा की शक्ति का साक्षात्कार नहीं कर सकता है और रोग का शिकार बनता है, आत्मा के कर्मों का का बोध होता है और साधना का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इन्द्रिय का सुख अनंत दुखों को देने वाला है। इस आत्मा की शक्ति को इन्द्रिय विजय साधना द्वारा उपयोग किया जाए तो चमत्कार हो सकते हैं। सक्षम मुनिजी और कौशल मुनिजी ने मांगलचरण किया। घनश्याम मुनिजी व अक्षत मुनिजी ने अपने विचार व्यक्त किए।

एशियाई शेरों की बढ़ती जनसंख्या : यादव

एक दशक में संख्या 523 से बढ़कर 891 हुई

नई दिल्ली/भाषा। भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने 'विश्व शेर दिवस-2026' के अवसर पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा कि एशियाई शेरों के संरक्षण में मिली सफलता, वन्यजीवों और जैव-विविधता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को गौरवान्वित करने वाला है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ''महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा से लेकर संरक्षण के प्रयासों को मज़बूत करने तक, भारत ने यह दिखाया है कि विकास और प्रकृति संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''विश्व शेर दिवस के मौके पर, आइए हम अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने का संकल्प दोहराएं और यह सुनिश्चित करें कि एशियाई शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2020 को 'प्रोजेक्ट लायन' की घोषणा की थी। भारत में शेरों के संरक्षण का कुल क्षेत्रफल 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

नौसेना प्रमुख समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के लिए मॉरीशस की यात्रा पर

नई दिल्ली/भाषा। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए सोमवार को मॉरीशस की चार दिवसीय यात्रा शुरू की। भारतीय नौसेना के अनुसार, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन मॉरीशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ ''पारस्परिक हित'' से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इनमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, दक्षता विकास और सैन्य सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। नौसेना ने कहा, ''यह यात्रा भारत की ओर से द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण साझेदार मॉरीशस के साथ रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए जारी प्रयासों का हिस्सा है।'' भारत और मॉरीशस के बीच लंबे समय से समुद्री साझेदारी है और भारतीय नौसेना प्रशिक्षण आदान-प्रदान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की संयुक्त निगरानी, बंदरगाह यात्राओं और जल सर्वेक्षण के जरिए इस द्वीपीय देश के राष्ट्रीय तटरक्षक बल के साथ नियमित रूप से सहयोग करती है। मॉरीशस भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल में नियमित रूप से भाग लेता रहा है, जिनमें बहुपक्षीय 'नौसैन्य अभ्यास मिलन', इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव शामिल हैं। ये पहल भारत के 'महासागर' दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

नीट प्रश्नपत्र लीक : अदालत ने 'लाई-डिटेक्टर टेस्ट' कराने की तीन आरोपियों की याचिका खारिज की

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक विशेष त्वरित अदालत ने सोमवार को तीन आरोपियों की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा से 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' और 'ब्रेन मैपिंग' कराने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने तीन आरोपियों मंगल लाल बीवाल, दिनेश बीवाल और विकास बीवाल की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट और 'ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल' (बीईएपी) जांच कराने की अनुमति मांगी थी। बीईएपी को ब्रेन मैपिंग भी कहा जाता है।

बेरोजगारी की समस्या दूर करें केंद्र और राज्य सरकारें : मायावती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों से खाली सरकारी पदों पर भर्ती शुरू करने तथा बेरोजगारी, महंगाई एवं गरीबों और कामकाजी लोगों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों से निपटने के लिए असरदार कदम उठाने की अपील की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की पिछली सरकार ने पुलिस और पंचायती राज विभागों में लगभग दो लाख 25 हजार नये सरकारी पद सृजित किये थे और भर्ती पर लगी रोक हटा दी थी, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के कई लाख लोगों को नौकरी मिली थी।

मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वह आखिरी बार 2007 से 2012 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद की सरकारें महंगाई, अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य सेवा, पिछड़ेपन, पलायन, महिलाओं की सुरक्षा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के प्रति उदासीन एवं लापरवाह रही हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉजपा के 36 दिनों तक चले आंदोलन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्य इस वक्त राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे बन गए हैं। उन्होंने मांग की कि सरकारें तुरंत गरीबों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं की चिंताओं का समाधान करें। सरकारी नौकरियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए उन्होंने राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचे जाने को रोकने और सभी सरकारी विभागों में खाली पदों पर भ्रष्टाचार और पेपर-लीक मुक्त भर्ती तुरंत शुरू करने की मांग की। मायावती ने कहा कि एक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने से लाखों परिवारों को इसका सीधा फायदा हो सकता है और आरक्षण के लाभों से काफी हद तक वंचित रखे गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को अधिक सुरक्षा मिल सकती है। उन्होंने कहा, ''सभी सरकारों को हर हाल में मुनाफाखोरी/लाभ कमाने वाली व्यापारिक सोच/प्रवृति को त्याग कर संविधान की सही मानवतावादी एवं कल्याणकारी नीति एवं सिद्धान्त को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अमल करके आगे बढ़ाना होगा।''

बसपा प्रमुख ने कहा कि जंतर मंतर पर आन्दोलित छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर संसद के वर्तमान सत्र में अब तक लगातार जारी गतिरोध को भी समाप्त किया जाना ज़रूरी है, ताकि बिना समुचित बहस और चर्चा के सरकारी विधेयकों को पारित होकर कानून बनने की प्रक्रिया पर विराम लग सके।

संसद में ममता के काफिले पर हमले का मुद्दा उठाने से रोका गया : तृणमूल सांसद हक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को संसद में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर कथित हमले का मुद्दा उठाया और इस घटना, पार्टी कार्यकर्ता की मौत तथा प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग पर तत्काल चर्चा की मांग की। पार्टी के एक सांसद ने यह जानकारी दी।

सांसद ने बताया कि हालांकि पार्टी को यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई। राज्यसभा सदस्य नदीमुल हक ने कहा कि पार्टी ने चर्चा के लिए कामकाज स्थगित करने की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया था लेकिन राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

नोटिस में रविवार को ममता बनर्जी के काफिले पर हुए कथित हमले का उल्लेख किया गया था।

ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पुलिस हिरासत में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता बिरजू केओट के परिवार से मिलने जा रही थीं, तभी यह घटना हुई थी।

सुविचार

हर दिन को विशेष बनाइए। अच्छे विचार सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, जीवन सफल और सार्थक बनेगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सपनों का बोझ और राजनीतिक मौन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं में जेन ज़ी का हमदर्द बनने की होड़ मच गई थी। हर कोई जोशीले बयान देकर खुद को क्रांतिकारी साबित करना चाहता था। वहीं, रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद सब खामोश हैं या बहुत नपे-तुले शब्दों में बयान दे रहे हैं। कथित क्रांति की जो ज्वाला दिल्ली में धधक रही थी, उसे रांची का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोहरे मापदंड क्यों? सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, या किसी अन्य पार्टी की, युवाओं से जुड़े कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो भविष्य में उनके लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होंगे। पेपरलीक तो सिर्फ एक मुद्दा है। मान लीजिए कि अगले 10 वर्षों तक कोई पेपरलीक नहीं होगा, लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जिन्हें किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी? उन युवाओं का क्या होगा जो बार-बार परीक्षाएं देंगे और नतीजे देखकर निराश होंगे? अगर भविष्य में वे भी कोई संगठन खड़ा कर हंगामा करेंगे तो सरकार क्या करेगी? भारत की आज़ादी के बाद दो तरह के चलन को काफी बढ़ावा मिला, जिसके नतीजे आज सरकारों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पहला, हर विद्यार्थी को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर बनने का सपना दिखाया जाता है। अगर नहीं बने तो क्या होगा - इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। दूसरा, पढ़ाई-लिखाई का मकसद आराम की ज़िंदगी समझा जाता है। सरकारों ने भी इन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं किया। किस राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वह इन दोनों बिंदुओं को चुनौती दे? जो ऐसा करेगी, अपना वोटबैंक गंवाएगी।

युवा भी सच सुनने को तैयार नहीं हैं। कई तो इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही इसका सपना दिखाया गया था। उन पर रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों आदि का दबाव होता है। उन्हें खुद से भी पूछना चाहिए- 'क्या मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता हूं? क्या यह मेरा फैसला है?' हमारे देश में ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे, जब कोई एक लड़का पटवारी या क्लर्क बन गया तो पूरा मोहल्ला इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी में लग गया। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के एक गांव में किसी लड़के का चयन वायुसेना में हो गया। इस घटना के बाद उसके ताऊ, चाचा, रिश्तेदारों, पड़ोसियों ... सबके लड़के वायुसेना भर्ती की तैयारी में जुट गए। एक लड़का जो सीए की पढ़ाई कर रहा था, वह भी उस मंडली में शामिल हो गया। हालांकि, उनमें से किसी का चयन वायुसेना में नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं, जिनकी पढ़ने-पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वे बीएड करके बैठे हैं कि एक दिन मास्टरजी बन जाएंगे। राजस्थान के गांव का एक व्यक्ति, जो नब्बे के दशक में बिहार से बीएड करके आया था, का आज तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन नहीं हुआ। उसने समय रहते कपड़ों की दुकान खोल ली, जो बढ़िया चल निकली। उसने बीएड इसलिए की थी, क्योंकि उसके पिता सरकारी शिक्षक थे, जिन्होंने बहुत मजे में नौकरी की थी। वे न कभी छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान देते थे, न कभी परीक्षा के नतीजों की परवाह करते थे। ठाठ से अपना साइड बिजनेस करते रहे और एक दिन सेवानिवृत्त हो गए। भरपूर पेंशन, समाज में रौब, रिश्तेदारों में विशेष सम्मान मिला सो अलग। उनका रुतबा देखकर कई लोगों ने बीएड की, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। अगर उस शिक्षक के बेटे ने बीएड करने के बजाय कपड़ों के व्यापार से संबंधित कोई प्रशिक्षण लिया होता तो अपने पेशे में बहुत उन्नति करता। हर विद्यार्थी डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, अफसर नहीं बन सकता और न ही हर विद्यार्थी शिक्षक बन सकता है। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो हर विद्यार्थी की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचाने और उसे उपयुक्त क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।

ट्वीटर टॉक

इंडियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो में न सिर्फ रिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बल्कि ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत के मैप से नॉर्थईस्ट को हटाने के खिलाफ आवाज़ भी उठाई और इसे ठीक करवाया। जिसकी तारीफ़ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी की है।

-भजनलाल शर्मा

वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर मैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के कोट्या भील पार्क में हुए प्रोग्राम में आदिवासी समाज के भाई-बहनों के बीच मौजूद था और उन्हें शुभकामनाएं दीं। आदिवासी समाज ने सदियों से जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान दिया है।

-ओम बिरला

शांति से अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे स्टूडेंटस पर पेलेट गन, कील लगी लाठियां, आंसू गैस छोड़ी गई। पुलिस ने जवान लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आईं। नाबालिगों की हड्डियां टूट गईं। मोदी सरकार ऐसे देती है सवाल का जवाब।

-राहुल गांधी

प्रेरक प्रसंग

शिव में विलीन होने की आध्यात्मिक रात्रि

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने शिवालयों में भक्तगण जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक, व्रत तथा विशेष पूजन-अर्चन, आराधना, भजन-कीर्तन आदि करते हैं। सावन महीने में सोमवार के व्रत का तो विशेष महत्व होता ही है, साथ ही इस महीने की शिवरात्रि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। वहीं, पवित्र भाव से सावन शिवरात्रि का पावन पर्व मनाने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनके समस्त रोग, शोक, दुख और कष्ट दूर होते हैं। इस वर्ष सावन शिवरात्रि का पावन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में ऐसी 12 शिवरात्रियां आती हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, इन सभी शिवरात्रियों में दो शिवरात्रियां विशेष मानी जाती हैंएक फाल्गुन महीने की और दूसरी श्रावण (सावन) महीने की शिवरात्रि।

सामयिक

विदेशी अंशदान कानून पर क्यों मचा है घमासान?

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

भारत में विदेशी धन प्राप्त करने वाली सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और जन कल्याणकारी संस्थाओं को नियंत्रित करने वाला विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। अब विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के बीच बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर विरोध करने वालों का आरोप है कि प्रस्तावित बदलाव सरकार को संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण का अधिकार दे सकते हैं और नागरिक समाज की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 का मूल उद्देश्य विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन के आगमन और उसके उपयोग को नियंत्रित करना है। भारत में अनेक सामाजिक संस्थाएं, धर्मार्थ संगठन, शैक्षणिक संस्थान और अन्य गैर सरकारी संगठन विदेशों से मिलने वाले अनुदान के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण और अन्य जन कल्याणकारी कार्य करते हैं। कानून यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विदेशी धन का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए न हो जो देश के राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हों। केंद्रीय गृह मंत्रालय की व्यवस्था के अनुसार विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली पात्र संस्थाओं को पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होती है तथा उन्हें प्राप्त धन और उसके उपयोग का हिसाब रखना पड़ता है।

वर्तमान विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 में प्रस्तावित वह व्यवस्था है जिसके तहत किसी संस्था का विदेशी अंशदान संबंधी प्रमाणपत्र समाप्त, रद्द या वापस हो जाने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियों के संबंध में एक विशेष व्यवस्था लागू होगी। विधेयक में ऐसी संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और निस्तारण के लिए नामित प्राधिकरण की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यही प्रावधान विरोध का सबसे बड़ा कारण बन गया है। आलोचकों का कहना है कि किसी संस्था का पंजीकरण रद्द होने या उसका नवीनीकरण न होने की स्थिति में उसकी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित होना गंभीर विषय है। उनके अनुसार किसी संस्था ने यदि वर्षों तक विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के संसाधनों से विद्यालय, चिकित्सालय, आश्रयगृह, प्रशिक्षण केंद्र या अन्य जनसेवा की संपत्तियां खड़ी की हैं तो केवल विदेशी अंशदान संबंधी अनुमति समाप्त होने के कारण उन संपत्तियों पर सरकारी अधिकार का प्रश्न उठना स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है। संसदीय विश्लेषण में भी यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रमाणपत्र समाप्त होने के साथ संपत्तियों के अधिकार और उपयोग को लेकर गंभीर कानूनी प्रश्न पैदा हो सकते हैं।

सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था में विदेशी अंशदान से निर्मित संपत्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र समाप्त होने के बाद क्या किया जाए, इसे लेकर पर्याप्त स्पष्ट और व्यवस्थित तंत्र नहीं था। प्रस्तावित कानून इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। सरकार के अनुसार यदि किसी संस्था को विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति नहीं है तो विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों को बिना किसी निगरानी के संस्था के पास छोड़ देना उचित नहीं होगा। इसलिए उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। विरोध का दूसरा महत्वपूर्ण कारण सरकार के अधिकारों के विस्तार से जुड़ा है। आलोचकों का कहना है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर पहले से ही अनेक प्रकार की निगरानी और अनुपालन संबंधी शर्तें लागू हैं। वर्ष 2026 में जारी नए नियमों के बाद संस्थाओं से उनकी गतिविधियों, कार्यक्षेत्र और प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी की अपेक्षा की गई है। आलोचकों को आशंका है कि इससे निगरानी केवल धन के स्रोत और उपयोग तक सीमित न रहकर संस्था की सामान्य गतिविधियों तक पहुंच सकती है।

यहां मूल प्रश्न पारदर्शिता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन का है। किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह विदेश से आने वाले धन की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि उसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध न हो। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विदेशी धन के माध्यम से राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक प्रभाव डालने की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए विदेशी अंशदान पर नियंत्रण की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार भी इसी आधार पर कड़े प्रावधानों को आवश्यक बताती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि नियम इतने कठोर न हो जाएं कि वास्तविक जनसेवा करने वाली संस्थाओं के लिए काम करना कठिन हो जाए। अनेक संस्थाएं विदेशी सहायता के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक विकास से जुड़े काम करती हैं। यदि प्रशासनिक नियम अत्यधिक जटिल हो जाएं या छोटी प्रक्रियात्मक भूलों के कारण संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई होने लगे तो इसका सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जिन्हें इन संस्थाओं से सहायता मिलती है। इसलिए आलोचक चाहते हैं कि कानून में कार्रवाई और दंड के बीच स्पष्ट अनुपात बना रहे।

विवाद का एक पहलू धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से कुछ चर्च संगठनों ने प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ आवाज उठाई है। मिजोरम में विभिन्न चर्च संगठनों ने प्रस्तावित संशोधन के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की है। उनका कहना है कि विदेशी सहायता से चलने वाली अनेक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करती हैं और नए प्रावधान उनके काम को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी विधेयक का विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस सहित विपक्ष का आरोप है कि प्रस्तावित कानून गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाने और सरकार की आलोचना करने वाली संस्थाओं पर दबाव बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। कांग्रेस ने 9 अगस्त 2026 को विधेयक के विरोध को लेकर अपना रुख और स्पष्ट किया तथा इसे जन विरोधी बताते हुए विरोध करने की बात कही। हालांकि ये राजनीतिक दलों के आरोप हैं और इन्हें कानून का प्रमाणित प्रभाव नहीं माना जा सकता।

विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें सरकार सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। उदाहरण के लिए विदेशी अंशदान संबंधी प्रमाणपत्र समाप्त होने के बाद संपत्तियों के प्रबंधन की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ अपराधों के लिए अधिकतम कारावास की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव भी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित संशोधन केवल कठोरता बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि कानून के कुछ हिस्सों में दंड व्यवस्था को कम करने और प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट करने का प्रयास भी करता है। वास्तविक चुनौती यह है कि विदेशी धन के नियमन को राजनीतिक असहमति के नियमन में बदलने से कैसे रोका जाए। किसी संस्था का विदेशी धन प्राप्त करना अपने आप में अपराध नहीं है। यदि वह कानून के अनुसार पंजीकृत है, धन का हिसाब रखती है और निर्धारित उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करती है तो उसे स्वतंत्र रूप से जनसेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं यदि कोई संस्था विदेशी धन का दुरुपयोग करती है, धन छिपाती है या देश के कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

इस दृष्टि से विदेशी अंशदान कानून का विरोध केवल विदेशी धन प्राप्त करने के अधिकार का प्रश्न नहीं है। यह सरकार की नियामक शक्ति, संस्थाओं की स्वायत्तता, संपत्ति के अधिकार, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न भी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का इस्तेमाल पारदर्शी और समान रूप से हो। कार्रवाई के स्पष्ट आधार हों, संस्था को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिले और संपत्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए न्यायिक संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था हो। भारत में मजबूत नागरिक समाज लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक संस्थाएं सरकार की प्रतिद्वंद्वी नहीं होतीं, बल्कि अनेक अवसरों पर वे सरकार के साथ मिलकर समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाती हैं। इसलिए विदेशी धन पर निगरानी और नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। विदेशी धन का दुरुपयोग राष्ट्रीय हित के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, लेकिन नियमों का अत्यधिक विस्तार भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती बन सकता है। अंततः विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 के विवाद को केवल सरकार बनाम विपक्ष या सरकार बनाम गैर सरकारी संगठनों के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि भारत विदेशी प्रभाव से अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हुए नागरिक समाज की वैध स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यक हैं, लेकिन उनके साथ निष्पक्षता, न्यायिक निगरानी और संस्थागत स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि कानून इन सभी पक्षों के बीच संतुलन स्थापित कर पाता है तो विदेशी अंशदान का नियमन अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन सकता है। लेकिन यदि नियंत्रण की शक्ति अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाती है और उसके दुरुपयोग से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं रहते, तो विरोध की आवाजें उठना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विदेशी अंशदान कानून को लेकर वर्तमान बहस केवल धन के स्रोत की निगरानी की बहस नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और नागरिक जीवन की सीमाओं और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की व्यापक बहस बन गई है।

नजरिया

बौद्धिक विरासत का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता की हकदार

संजीव ठाकुर

मोबाइल : 9009 415 415

किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति, आधुनिक तकनीक, चमचमाते शहरों और ऊँची इमारतों से नहीं होती। राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसकी स्मृतियों, संस्कारों, अनुभवों और आने वाली पीढ़ियों के सपनों में होती है। जिस समाज ने अपने अतीत को सम्मान दिया, वर्तमान को संवारा और भविष्य को संस्कार दिए, वही समाज दीर्घकाल तक अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रख सका। बुजुर्ग हमारी बौद्धिक विरासत हैं, महिलाएँ हमारी सांस्कृतिक एवं पारंपरिक शक्ति हैं और बच्चे राष्ट्र के सशक्त भविष्य की आधारशिला हैं। इन तीनों को अलग-अलग देखने के बजाय एक ऐसी जीवन-श्रृंखला के रूप में देखना होगा, जिसमें अतीत का अनुभव वर्तमान के संस्कारों से होकर भविष्य की संभावनाओं में बदलता है। आज हम सूचना के ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ एक क्लिक पर हजारों सूचनाएँ उपलब्ध हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ही क्षणों में जटिल प्रश्नों के उत्तर दे सकती है, लेकिन जीवन के अनुभव का कोई डिजिटल विकल्प नहीं है।

एक बुजुर्ग ने जीवन में जितने उतार-चढ़ाव देखे हैं, वे किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं मिल सकते। उन्होंने अभाव का समय देखा, संघर्ष किया, रिश्तों को निभाया, सामाजिक परिवर्तन को अपनी आँखों के सामने घटित होते देखा और अपने अनुभव से परिवारों को संभाला। इसलिए बुजुर्गों को केवल आयु के आधार पर निर्भर व्यक्ति समझना उनके व्यक्तित्व और समाज में उनके योगदान को छोटा करना है।भारतीय परंपरा ने सदैव वृद्धों के अनुभव को महत्व दिया। मनुस्मृति में कहा गया है- अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।। अर्थात जो व्यक्ति वृद्धों का सम्मान और सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। आज इस श्लोक को केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं, बल्कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भी समझने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के पास अनुभव की वह पूँजी है, जिसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाना राष्ट्र की बौद्धिक संपदा का संरक्षण है। दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन में संयुक्त परिवारों के विघटन, रोजगार के लिए पलायन और व्यस्त जीवनशैली ने बुजुर्गों के सामने अकेलेपन की समस्या खड़ी की है। कई बार घर में रहते हुए भी वे संवाद से बाहर हो जाते हैं।

समस्या का समाधान केवल वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम आवश्यकता की स्थिति में उपयोगी संस्था हो सकता है, लेकिन परिवार का विकल्प नहीं। बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता सम्मान, संवाद, अपनत्व और निर्णयों में सहभागिता की है।महिलाएँ संस्कृति की मौन वाहक होती हैं।भारत की सांस्कृतिक परंपरा को यदि किसी ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखा है तो उसमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बच्चे की पहली भाषा, पहला संस्कार, पहली प्रार्थना, पहला लोकगीत और परिवार के अनेक रीति-रिवाज अक्सर माँ और दादी-नानी के माध्यम से ही बच्चे तक पहुँचते हैं। इसलिए महिला को केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित करके देखना उसकी वास्तविक भूमिका को कम करके देखना है।स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर उसकी महिलाओं की स्थिति है। जिस देश की महिलाएँ शिक्षित, सुरक्षित, स्वावलंबी और निर्णय लेने में सक्षम होंगी, वहाँ परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। भारतीय इतिहास में अहिल्याबाई होल्कर, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले और अनेक महिलाओं ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल संवेदना की प्रतीक नहीं, बल्कि नेतृत्व, संघर्ष, ज्ञान और परिवर्तन की शक्ति भी है। इसलिए महिलाओं के सम्मान की बात केवल भावनात्मक विषय नहीं होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और समान अवसर ये महिला सशक्तीकरण के वास्तविक आधार हैं। यदि बुजुर्ग अनुभव हैं और महिलाएँ संस्कारों की वाहक हैं, तो बच्चे उस अनुभव और संस्कार के भविष्य हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। वे बच्चों को देश की भावी शक्ति मानते थे।

उनका प्रसिद्ध विचार था कि आज के बच्चे ही कल का भारत बनाएँगे। यह विचार हमें याद दिलाता है कि बच्चों की शिक्षा और परवरिश केवल माता-पिता की निजी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है।।आज बच्चों के सामने नई चुनौतियाँ हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल मनोरंजन ने ज्ञान के अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन इनके साथ ध्यान भटकने, सामाजिक अलगाव और वास्तविक संवाद कम होने जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। बच्चों को केवल महँगे विद्यालय और आधुनिक उपकरण देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समय, संस्कार, अनुशासन, संवेदना, खेल, प्रकृति और परिवार के बुजुर्गों का सान्निध्य भी चाहिए। एक बच्चा जब दादा-दादी से कोई कहानी सुनता है तो वह केवल कहानी नहीं सुन रहा होता; वह परिवार का इतिहास, भाषा, लोकस्मृति और जीवन-दर्शन ग्रहण कर रहा होता है।

आज हमारे सामने एक विचित्र स्थिति है। बुजुर्गों के पास अनुभव है, युवाओं के पास ऊर्जा है और बच्चों के पास भविष्य की संभावनाएँ हैं, लेकिन इन तीनों के बीच संवाद लगातार कम हो रहा है।।बुजुर्ग कहते हैं आज की पीढ़ी हमारी बात नहीं सुनती। युवा कहते हैं बुजुर्ग हमें समझते नहीं। और बच्चे कहते हैं हमारे पास किसी के पास बैठने का समय नहीं।

यदि यह दूरी बढ़ती रही तो हम केवल पारिवारिक संबंध नहीं खोएँगे, बल्कि पीढ़ियों के बीच ज्ञान का हस्तांतरण भी कमजोर होगा। इसलिए घर में ऐसा वातावरण बनना चाहिए जहाँ दादा-दादी बच्चों से बात करें, महिलाएँ परिवार की सांस्कृतिक स्मृतियों को आगे बढ़ाएँ और युवा दोनों पीढ़ियों के अनुभव तथा ऊर्जा को जोड़ने का काम करें। हमें यह भी समझना होगा कि संरक्षण का अर्थ अतीत को ज्यों का त्यों ढोना नहीं है। परंपरा वही जीवित रहती है जो समय के साथ स्वयं को उपयोगी बनाती है। बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की तकनीकी दक्षता मिल जाए तो परिवार अधिक सक्षम बन सकता है। महिलाओं की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक शिक्षा मिल जाए तो समाज अधिक संवेदनशील और आत्मनिर्भर बन सकता है। बच्चों को आधुनिक विज्ञान के साथ भारतीय जीवन-मूल्यों की समझ मिल जाए तो भविष्य अधिक संतुलित होगा।

महात्मा गांधी का विचार था कि ऐसा जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा जीना है। इस विचार में पीढ़ियों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण की गहरी भावना छिपी हैसरकारें बुजुर्गों के लिए योजनाएँ बना सकती हैं, महिलाओं के लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था दे सकती हैं तथा बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण की योजनाएँ चला सकती हैं। लेकिन इन सबकी सफलता तभी संभव है जब समाज की मानसिकता बदले।बुजुर्गों को दया नहीं, सम्मान चाहिए। महिलाओं को केवल सुरक्षा नहीं, समान अवसर और निर्णय की स्वतंत्रता चाहिए। बच्चों को केवल सुविधाएँ नहीं, समय, संस्कार और सुरक्षित भविष्य चाहिए।

हमें यह समझना होगा कि जिस घर में बुजुर्ग सम्मानित होते हैं, वहाँ अनुभव सुरक्षित रहता है; जिस घर में महिला सम्मानित होती है, वहाँ संस्कृति और संवेदना मजबूत होती है; और जिस घर में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, वहाँ भविष्य सुरक्षित होता है। बुजुर्ग अतीत की स्मृति हैं, महिलाएँ वर्तमान की सांस्कृतिक शक्ति हैं और बच्चे भविष्य की संभावना। इन तीनों को जोड़ने वाला मजबूत पारिवारिक और सामाजिक तंत्र ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए आज आवश्यकता केवल विकास की नहीं, पीढ़ियों को जोड़ने वाले विकास की है। बुजुर्गों की स्मृतियों को सुरक्षित रखिए, महिलाओं की शक्ति को सम्मान दीजिए और बच्चों के सपनों को पंख दीजिए।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

'आठ फीट 10 इंच के बाल...'

हल्द्वानी की रेणु ने 11 साल की मेहनत के बाद बनाया विश्व रिकॉर्ड

हल्द्वानी (उत्तराखंड)/भाषा। आमतौर पर लंबे बाल किसी महिला की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी की रेणु धरियाल के लिए यही लंबे बाल अब उनकी पहचान, जुनून और विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। आठ फीट 10 इंच यानी 271.50 सेंटीमीटर लंबे बालों के साथ रेणु ने 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में अपना नाम दर्ज करवाकर हल्द्वानी को दुनिया के नक्शे पर अंकित कर दिया है।

मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले की रेणु वर्तमान में हल्द्वानी के कठघरिया क्षेत्र में रहती हैं। बचपन में लंबे बाल रखने की उनकी एक छोटी-सी ख्वाहिश वक्त के साथ जुनून में बदल गई। उन्होंने 2015 में अपने बालों को बढ़ाना शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 11 वर्षों तक लगातार देखभाल, धैर्य और मेहनत का नतीजा आज उनके सिर पर दुनिया के सबसे लंबे बालों के रूप में मौजूद है। रेणु के बालों की लंबाई देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन यह कोई दावा भर नहीं, बल्कि 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' की प्रक्रिया से गुजरी प्रमाणित उपलब्धि है।

रेणु ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि अप्रैल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' की टीम हल्द्वानी पहुंची और उनके बालों की विधिवत जांच एवं माप ली जिसमें उनकी लंबाई 271.50 सेंटीमीटर दर्ज की गई। इसी के साथ रेणु का नाम सबसे लंबे वालों वाली जीवित महिला के रूप में रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले, सबसे लंबे बालों का यह रिकॉर्ड यूक्रेन की आलिया नासिरोवा के नाम दर्ज था जिनके बालों की लंबाई 257.33 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी। इतने लंबे बाल रखना जितना सुनने में रोमांचक लगता है, उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल है। हालांकि, 35 वर्षीय रेणु के लिए बालों की देखभाल रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि बालों को जमीन से दूर रखने के लिए उन्हें विशेष तरीके से चोटी बनानी पड़ती है जबकि बाल धोने, सुखाने और उन्हें सुलझाने में कई घंटे लग जाते हैं।

रेणु के मुताबिक, लंबे बालों के कारण उन्हें रोजमर्रा के कामों में भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है, इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने इस जुनून को बोझ नहीं माना। उन्होंने कहा कि लंबे बालों को बनाए रखने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए उनके बाल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हैं बल्कि वे भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं जहां हमेशा से उन्हें सुंदरता और नारीत्व का प्रतीक माना जाता रहा है। रेणु सिर्फ विश्व रिकॉर्डधारक ही नहीं हैं, बल्कि एक 'कंटेंट क्रिएटर' और यूट्यूबर के रूप में भी उनकी पहचान है। वह अपने लंबे बालों की देखभाल, अनुभव और ब्यूटी टिप्स से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती रहती हैं।

पीओके में हिंसा और धांधली के आरोपों के बीच हुआ तीसरे चरण का मतदान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हिंसा और धांधली के आरोपों के बीच सोमवार को चार निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण का मतदान हुआ। पुंछ डिवीजन के बाग और हवेली जिलों में मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ, जबकि सात निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए।

कुछ इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आईं। क्षेत्र के निर्वाचन आयोग ने चार निर्वाचन क्षेत्रों के 803 मतदान केंद्रों में से अधिकांश को 'संवेदनशील' या 'अति संवेदनशील' घोषित किया था। निर्वाचन आयोग ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता के कारण तीसरे और अंतिम चरण में पुंछ डिवीजन की सात सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया था।

भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। नई दिल्ली यह भी कहती है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा'' कर रखा है। क्षेत्र की तथाकथित विधानसभा के लिए चुनाव के पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 27 जुलाई और दो अगस्त को मतदान हुआ था। इन दोनों चरणों में हिंसक प्रदर्शनों और बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों के कारण चुनाव प्रभावित हुए थे। सरकार समर्थित पीएमएल-एन ने दोनों चरणों में जीत हासिल की और 24 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केंद्र में उसकी गठबंधन सहयोगी पीपीपी ने कुल 34 सीटों पर हुए चुनाव में 10 सीटें जीतीं। कुल 45 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है।

पीएमएल-एन क्षेत्र में सरकार बनाने की तैयारी में है। पार्टी ने घोषणा की है कि उसके प्रमुख नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय करेंगे। पीपीपी ने तीसरे चरण में पीएमएल-एन पर बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया है। पीपीपी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि बन्नी मरासिरा इलाके की ओर जाने वाली सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया था और आरोप लगाया कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर पीएमएल-एन समर्थक अवैध रूप से मतपत्रों पर मुहर लगा रहे थे।

पीपीपी ने कहा, ''अधिकारी, मतदाता, मतदान एजेंट और पार्टी कार्यकर्ता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और यह नहीं देख पा रहे हैं कि अंदर क्या किया जा रहा है।'' पार्टी ने यह भी कहा कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मियों के समय पर नहीं पहुंचने के कारण मतदान समय पर शुरू नहीं हो सका। उसने यह भी दावा किया कि कुछ मतदान केंद्रों से पीपीपी के मतदान एजेंटों को जबरन बाहर निकाल दिया गया, जहां पीएमएल-एन समर्थक मतपत्रों पर मुहर लगा रहे थे।

जेएएसी ने दावा किया है कि जून के पहले सप्ताह से अब तक करीब 400 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। इसके अलावा उसका दावा है कि 27 जुलाई को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान 40 से अधिक लोग मारे गए थे।

तिरंगा यात्रा

स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सोमवार को नई दिल्ली में गांधी स्मृति द्वारा राजघाट से लाल किले तक आयोजित 'तिरंगा यात्रा' में भाग लेते स्कूली बच्चे।

'मुसाफिर कैफे' में बेबाक लड़की बनीं वेदिका पिंटो

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में सुधा नाम की बेबाक लड़की का किरदार निभाया है, जो ज्यादा विचार नहीं करती, बल्कि अपनी अंतरात्मा और इंस्टिंक्ट (सहज ज्ञान) पर भरोसा करती है। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि वे सुधा की तरह बनना चाहती हैं। वेदिका पिंटो ने बताया कि उनमें और सुधा में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा, काश मैं सुधा जैसी होती। हमारे बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं, जबकि सुधा शायद ही कभी किसी चीज पर ज्यादा सोचती है। वह अपने मन की सुनती है और उसे जो कुछ भी करना है, उसके लिए वह बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। अभिनेत्री ने बताया कि इस किरदार को निभाते वक्त उन्होंने सुधा की तरह मन की सुनने की कोशिश की थी।इससे पहले अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'निशांची' में डांसर 'रिंकू' नाम की दबंग और रंगीली लड़की का किरदार अदा किया था। अभिनेत्री से जब आईएएनएस ने अनुराग कश्यप के साथ काम करने को लेकर पूछा, फिल्म निशांची में अनुराग कश्यप के साथ आपने उनसे ऐसा क्या सीखा जो कोई एक्टिंग स्कूल नहीं सिखा सकता? अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने कहा, अनुराग सर के साथ काम करने के दौरान मुझे एक्टिंग के साथ-साथ जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला था, जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि फिल्म 'निशांची' और अनुराग सर के साथ काम करने के बाद मुझमें खुद को स्वीकार करना आया और यही मेरे सफर का सबसे बड़ा सबक रहा है।अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में नेटवर्किंग जरूरी है। उन्होंने यह भी माना कि नेटवर्किंग की वजह से ही उन्हें अनुराग कश्यप के साथ काम करने का मौका मिला। अभिनेत्री ने कहा, मैं बहुत समय से अनुराग सर के साथ काम करना और उनसे मिलना चाहती थीं। मेरे मैनेजर ने आखिरकार उनके साथ मीटिंग अरेंज की और हमारी बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने मुझमें कुछ ऐसा देखा, जिसकी वजह से आखिरकार निशांची मिली। अगर वह मीटिंग नहीं होती तो शायद मुझे वह फिल्म नहीं मिलती। इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है क्योंकि लोग आपको किसी रोल के लिए कंसीडर करने से पहले आपको जानना जरूरी समझते हैं।

अभिनेत्री से एक और सवाल किया, आजकल सोशल मीडिया पर दिखना बहुत जरूरी माना जाता है। क्या आपको लगता है कि दिखना एक्टिंग टैलेंट जितना ही जरूरी हो गया है? अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने कहा, एक समय था जब मैं सुनती थी कि कास्टिंग फॉलोअर्स या पॉपुलैरिटी पर निर्भर करती है। मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है, लेकिन मैं हमेशा एक्टिंग और सोशल मीडिया को अलग रखती हूं क्योंकि एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है।

'टॉक्सिक' ट्रेलर आउट

बैंगलूरु/एजेन्सी

काफी इंतज़ार के बाद आखिरकार टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स का ट्रेलर आ गया है, जो एक ऐसे फैले हुए दुनिया की पहली झलक देता है जहाँ कैओस का टकराव कैओस से होता है, वफादारियाँ टेस्ट होती हैं और हर किरदार अपनी अलग कहानी लेकर चलता है। रॉकिंग स्टार यश की अगुवाई में ये ट्रेलर टॉक्सिक को एक बड़े स्केल वाली, लार्जर दैन लाइफ मैग्नम ओपस के रूप में पेश करता है, जिसमें हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ एक इमोशन से भरी कहानी हैजो प्यार, पावर की भूख, धोखा और रिडेम्पशन पर टिकी है। दमदार विज़ुअल्स, धमाकेदार एक्शन, लेयर्ड कैरेक्टर्स और इंटेंस रिश्तों के साथ ये ट्रेलर एक ऐसे गैंगस्टर सागा का वादा करता है जो जितना स्पेक्टैक्युलर है, उतना ही इमोशन से भरा हुआ भी है। टॉक्सिक के दिल में बसी है राया और उसके बेटे टिकट के बीच की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जो इस बड़े गैंगस्टर वर्ल्ड को एक इमोशनल गहराई देती है। ट्रेलर में रिश्तों और दुश्मनियों

का एक पूरा जाल भी दिखाया गया है, जिसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी के किरदारों की झलक मिलती है। पूरी स्टारकास्ट जबरदस्त असर छोड़ती है, जहाँ हर कलाकार अपने किरदार में अलग शेड्स और इंटेंसिटी लेकर आता है।

अवॉर्ड-विनिंग फिल्ममेकर गीथू मोहनदास अपनी यूनिक स्टोरीटेलिंग और विज़ुअल स्टाइल के साथ टॉक्सिक में एक इमर्सिव और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया रचती हैं। ट्रेलर में यशी यश का जबरदस्त फेस-ऑफ देखने को मिलता है, जहाँ यश राया और टिकट दोनों किरदार निभा रहे हैंएक बाप और बेटा, जो एक धमाकेदार टकराव के दो अलग किनारों पर खड़े हैं। इस सेंट्रल लड़ाई के अलावा, ट्रेलर फिल्म की एम्बिशियस वर्ल्ड-बिल्डिंग भी दिखाता हैहाई-ऑक्टेन एक्शन, थ्रिलिंग सीक्वेंस, शानदार प्रोडक्शन डिजाइन और एटमॉस्फेरिक विज़ुअल्स के जरिए। सिनेमैटोग्राफी इस डार्क और टेक्सचर्ड दुनिया को और भी विज़ुअली अरेस्टिंग बनाती है, जबकि गीथू एक्शन, इमोशन और कैरेक्टर डायनामिक्स को मिलाकर एक एम्बिशियस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पेश करती हैं।इंग्लिश और कन्नड़ में एक साथ शूट की गई टॉक्सिक को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब्ड वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा, ताकि इसकी एक्शन और थ्रिल से भरी दुनिया हर भाषा के दर्शकों तक पहुँच सके। गीथू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। घतछ प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस द्वारा निर्मित ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

मैं चीजों को नेचुरल तरीके से होने दूंगी : सुरभि चंदना

मुंबई/एजेन्सी

एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने एक्ट्रेस और महिला सेलिब्रिटीज के बीच एग्स फ्रीज़ करने के बढ़ते ट्रेंड पर अपनी राय दी। सुरभि ने कहा कि हालांकि वह उन सभी महिलाओं का समर्थन करती हैं जो अपने एग्स फ्रीज करने का फैसला करती हैं, लेकिन उन्हें खुद ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वह चीजों को उनके नैचुरल तरीके से होने देने में विश्वास रखती हैं। 'नागिन' एक्ट्रेस से पूछा गया, आजकल बहुत सी एक्ट्रेस अपने एग्स फ्रीज करवा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है?इस पर जवाब देते हुए सुरभि ने अपनी बहन का उदाहरण दिया, जिन्होंने बिना किसी मेडिकल मदद के 39 साल की उम्र में मां बनने का अनुभव लिया।उन्होंने आईएएनएस को बताया, मेरी बहन ने 39 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया। वह अब दो साल का है - और यह एक नॉर्मल डिलीवरी थी।

मैं भी इसमें विश्वास रखती हूं, और जो लोग एग्स फ्रीज करना जरूरी समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था, अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत ज्यादा हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।मुझे लगता है कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आता है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहन, जिसकी नौकरी में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और जिसका शरीर बहुत ज्यादा तनाव से गुजरता है, अगर वह नैचुरली बच्चे को जन्म दे सकती है, तो मैं भी नैचुरल तरीका ही अपनाना चाहती हूं।सुरभि ने आगे माना कि उन्हें अभी भी एग्स फ्रीज करने की प्रक्रिया से जुड़े हार्मोनल असंतुलन से थोड़ा डर लगता है।

उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि हम कब प्लान करेंगे, लेकिन यह सही समय आने पर होगा। जब भी ऐसा होगा, यह भगवान का तोहफा होगा। काम की बात करें तो, सुरभि ने अपने होम बैनर 'फील गुड स्टूडियोज' के तहत नए बालाजी डिजिटल शो 'इश्क दम और इडली रसम' के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू किया है।

पूजा

पवित्र सावन (श्रावण) महीने के दौरान सोमवार, को लखनऊ के बाराशिवाला मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु।

केबीसी के ग्रैंड प्रीमियर में होगी 'बंटवारा 1947' की पूरी स्टारकास्ट

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी पीरियड ड्रामा 'बंटवारा-1947' की पूरी स्टारकास्ट अभिनेता अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के ग्रैंड प्रीमियर में आमिर खान के साथ शिरकत करेगी। शो मेकर्स ने प्रीमियर का छोटा-सा क्लिप शेयर कर इस बात की जानकारी दी। सभी कलाकार होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ इस क्विज-बेस्ड रियलिटी शो में अपनी आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' का प्रमोशन करते नजर आएंगे। चैनल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया प्रोमो शेयर किया है। इसमें आमिर खान मस्ती के मूड में बिग बी से इस सीजन की थीम 'सोचना पड़ेगा' के बारे में सवाल करते दिख रहे हैं। आमिर कहते हैं, आपने प्रोमो में कहा है 'सोचना पड़ेगा', तो क्या सोचना पड़ेगा?इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने अपने खास अंदाज में कहा, इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सोचना पड़ता है न, भाईसाब।आमिर ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, सोचना पड़ेगा, सर... वाकई सोचना पड़ेगा।इस एपिसोड में सनी देओल पहली बार कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर नजर आएंगे। बता दें कि सनी का अमिताभ बच्चन के साथ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता उनके पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के जरिए दशकों पुराना है।

अमिताभ और धर्मेंद्र ने साथ में कई यादगार फिल्में की हैं, जिनमें 'शोले', 'चुपके चुपके' और 'राम बलराम' शामिल हैं। वे हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित समकालीन कलाकारों में से एक हैं।फिल्म 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और यह आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म में सनी देओल, करण देओल, अली जफर, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अभिमन्यु सिंह अहम किरदारों में हैं।फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है। यह उन आम लोगों की जिंदगी को दिखाती है जो इस विभाजन से प्रभावित हुए थे।

कहानी में एक हिंदू परिवार को दिखाया गया है जो लाहौर से भारत आता है और उन्हें एक हवेली मिलती है जो पहले एक मुस्लिम परिवार की थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि उस हवेली में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला अभी भी रह रही है। इसी स्थिति से इंसानी रिश्तों, भावनाओं और संघर्ष की एक गहरी कहानी पेश की जाएगी। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

कम उम्र में शोहरत, फिर विवादों ने घेरा : हंसिका मोटवानी

मुंबई/एजेन्सी

हंसिका मोटवानी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बचपन में टीवी की दुनिया में कदम रखा, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाई, बॉलीवुड में बड़े सितारों के साथ काम किया और फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर लीड एक्ट्रेस अलग जगह बना ली। लेकिन, जितनी तारीफ हंसिका के काम की होती है, उससे ज्यादा चर्चे उनकी निजी जिंदगी को लेकर होते हैं। वह किसी न किसी चीज को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। 9 अगस्त 1991 को मुंबई में जन्मीं हंसिका ने बहुत छोटी उम्र में ही कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया था। टीवी के मशहूर शो 'शाका लाका बूम बूम' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आने के बाद वह घर-घर में पहचानी जाने लगीं। इसके बाद उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे लोकप्रिय सीरियल में भी काम किया। हंसिका की अगली बड़ी छलांग बॉलीवुड में हुई। ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म 'कोई मिल गया' में उनकी मौजूदगी को दर्शकों ने पसंद किया।कुछ समय बाद हंसिका ने साउथ सिनेमा का रुख किया। उन्होंने तेलुगु फिल्म 'देसमुदुरु' से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया। उस समय उनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन फिल्म में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान भी मिला। इसके बाद तमिल फिल्मों में भी उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। 'एंगेयुम काधल' और 'ओरु कल ओरु कन्नाड़ी' जैसी फिल्मों ने उन्हें दक्षिण भारतीय दर्शकों के बीच मजबूत पहचान दिलाई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करके उन्होंने अपनी बहुभाषी पहचान बनाई। एक चुलबुली और मासूम लड़की के किरदारों से शुरुआत करने वाली हंसिका ने धीरे-धीरे अलग तरह के रोल भी किए।

हंसिका का करियर जितना तेजी से आगे बढ़ा, उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं भी उतनी ही तेज होती गईं। एक समय उनकी बदली हुई शारीरिक बनावट को लेकर तरह-तरह की बातें कही गईं और उन पर हार्मोनल इंजेक्शन लेने के आरोप लगे। हंसिका ने इन आरोपों को खारिज किया था।इसके अलावा, एक कथित एमएमएस के वायरल होने के बाद भी उनका नाम चर्चा में आया। हालांकि, हंसिका ने साफ किया था कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की वह नहीं थी। बावजूद इसके, इस विवाद ने काफी समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ा।हंसिका की निजी जिंदगी का सबसे ज्यादा चर्चित अध्याय उनकी शादी रही। उन्होंने 4 दिसंबर 2022 को बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया से शादी की। राजस्थान के जयपुर में हुई इस शाही शादी की तस्वीरों और वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरीं। उनकी शादी पर 'हंसिका लव शादी ड्रामा' नाम की एक वेब सीरीज भी बनी है। हालांकि शादी की घोषणा के साथ ही विवाद शुरू हो गया। सोहेल की यह दूसरी शादी थी और उनकी पहली पत्नी रिंकी बजाज हंसिका की दोस्त थीं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर हंसिका पर कई तरह के आरोप लगाए गए। हंसिका ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोहेल और रिंकी के रिश्ते में क्या हुआ, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं था। हालांकि, हंसिका और सोहेल का रिश्ता भी ज्यादा समय चल नहीं पाया। दोनों ने तलाक ले लिया है।

जो श्रेष्ठ मिला है, उसकी कदर कीजिए : कपिल मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहाँ चूलै स्थित लक्ष्मी महल में चातुर्मासार्थ विराजित क्रांतिकारी श्री कपिल मुनि जी म.सा. ने सोमवार को प्रवचन के दौरान कहा कि वर्तमान में हमारे पास जो भी अच्छा, श्रेष्ठ और दुर्लभ है, उसकी कदर कीजिए। क्योंकि जो आज उपलब्ध है, जरूरी नहीं कि कल भी उपलब्ध रहे। समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से अवसर वापस नहीं आता। विशेष रूप से यदि पुण्ययोग से श्रेष्ठ धर्म और गुरु भगवंतों का समागम मिला है, तो इसे सामान्य उपलब्धि मत समझिए। संसार की हजारों उपलब्धियाँ मिलकर भी उस आध्यात्मिक सौभाग्य की बराबरी नहीं कर सकतीं। धन मिलना सरल हो सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, सुख-सुविधाएँ जुटाई जा सकती हैं; लेकिन सत्य का मार्ग दिखाने वाला गुरुदेव और धर्म के प्रति जागृत करने वाला अवसर जीवन में बार-बार नहीं मिलता। आज भगवान की वाणी आपके कानों तक पहुँच रही है, आत्मकल्याण की प्रेरणा मिल रही है तो इसे कल पर मत टालिए। धर्म को सुनने और धर्म को जीने का समय आज है। आत्मा के लिए जागने का समय आज है। यदि आज हम इसकी उपेक्षा करते रहे तो हो सकता है कल परिस्थितियाँ बदल जाएँ। गुरु भगवंतों का समागम न रहे, शरीर साथ न दे, समय न मिले या मन में वैसी श्रद्धा न रहे। फिर मनुष्य कहेगा-काश! उस समय मैंने इस अवसर का लाभ उठाया होता। लेकिन काश से जीवन नहीं बदलता।

उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा के लिए भी समय निकालिए। चौबीस घंटे में से यदि आप अपने आत्मकल्याण के लिए एक घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की है। यह संसार प्रतिध्वनि से भरा हुआ है आप जो देते हैं, वही लौटकर आपके पास आता है। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। इस मौके पर संयोजक अशोक छाजेड़, वड़पलनी संघ के अध्यक्ष प्रकाशचंद बोहरा, हितेश कोचर,शांतिलाल लोढ़ा, सागरमल कोठारी, अमरचंद कोठारी नीलमचंद बाफना, सुनील रांका आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

ऑल इंडिया जैनोलॉजी कोर्स की परीक्षा संपन्न

चेन्नई/दक्षिण भारत। यहां आदिनाथ जैन ट्रस्ट द्वारा संचालित ऑल इंडिया जैनोलॉजी कोर्स की परीक्षाएँ 2 एवं 6 अगस्त को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। यह जैनोलॉजी कोर्स प्रख्यात विद्वान डॉ. सागरमल जैन एवं कुमारपालभाई वी. शाह के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।

चेन्नई में यह परीक्षा चूलै, वेपेरी, पुरुसवाल्कम, किलपॉक, नॉर्थ टाउन (बिन्नी) सहित अनेक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। लगभग 4000 विद्यार्थियो ने देश भर में परीक्षा दी।

वर्तमान में इस कोर्स से देशभर के 260 से अधिक अध्ययन केंद्र, 32,000 से अधिक विद्यार्थी तथा लगभग 200-250 साधु-साध्वी भगवंत जुड़े हुए हैं।

आहार की आसक्ति मिटाने के लिए ईश्वर की आराधना आवश्यक : जयतिलक मुनि

चेन्नई/दक्षिण भारत। एसएस जैन संघ साहुकार पेट के तत्वाधान में जैन भवन प्रांगण में विराजित जयतिलक मुनिजी म.सा. ने प्रवचन में कहा किभगवान महावीर स्वामी के अनुसार आहार की आस्क्ति को मिटाने के लिए भगवान की आराधना आवश्यक है। आहार भी इच्छाव रस इन्द्रियों को वस मे करने के लिए तप त्याग करना जरूरी है। इसके साथ सोदर्य की भी वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए।

गुरुदेव ने फरमाया कि तपस्या के साथ मन की इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना चाहिए नहीं तो कर्मी की निर्जरा नहीं हो सकती है। आहार का त्याग करना ही पूर्ण कर्मो की निर्जरा नहीं है बल्कि संसार का त्याग करना पाँच इन्द्रियों व तीन विषयों को वश में करना ही सच्ची तपस्या है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसे तपाना पड़ेगा। आशक्ति को घटाने के लिए शरीर को यातना देनी चाहिए।

इच्छाओं को घटाने के लिए तप, त्याग, तपस्या आदि करनी चाहिए। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए पाप का त्याग करना पडता है।

प्रभु को मन-मंदिर में लाओ, दुःख, दोष, दुर्बुद्धि स्वयं दूर हो जाएंगे : पं. ज्ञानबोधि विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

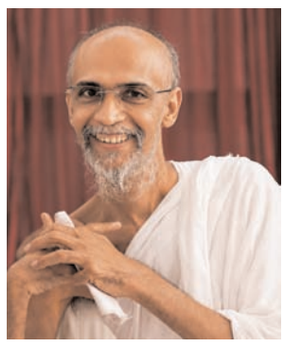

चेन्नई। श्री वेपेरी जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित आचार्य श्री कुलबोधि सूरीश्वरजी म. के शिष्य पन्यास ज्ञानबोधि विजयजी म. ने सोमवार को श्री भुवनभानुसूरी प्रवचन मंडप में 'ललित विस्तरा' ग्रंथ की विवेचना करते हुए कहा कि चैत्यवंदन को भावपूजा कहा गया है। द्रव्यपूजा का जितना महत्व है, उतना ही भावपूजा का भी है। प्रभु के समक्ष की गई द्रव्यपूजा चेक लिखने के समान है, जबकि चैत्यवंदन उस चेक पर हस्ताक्षर करने के समान है। उन्होंने कहा कि हम द्रव्यपूजा तो करते हैं, लेकिन चैत्यवंदन के भाव से अक्सर वंचित रह जाते हैं।

पंन्यासजी ने कहा कि प्रार्थना और याचना में अंतर समझाते हुए कहा कि परमात्मा से मांगना प्रार्थना है, जबकि अन्य देवी-देवताओं से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगना याचना है। गणधर भगवंतों द्वारा रचित जयवीराय में प्रभु से दुःख दूर करने के साथ-साथ अपने दोषों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। उन्होंने कहा, प्रभु ने जो पाया है, वही हमें मांगना है; प्रभु ने जो छोड़ा है, उसे मांगना नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरु के पास जाएं तो पहले गुरु-वंदन और फिर सुख-साता पूछनी चाहिए। प्रभु ने साधना के माध्यम से कर्मों का क्षय किया, इसलिए उनकी जयजयकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनशासन दुःखों से भागना नहीं, बल्कि दुःखों के सामने अपनी मनःस्थिति पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं और दुःख में उन्हें याद करते हैं। वास्तव में परिस्थिति को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन मनःस्थिति को बदला जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अर्जुन की विजय के पीछे श्रीकृष्ण सारथी बने, उसी प्रकार हमें भी प्रभु को अपने जीवन का सारथी बनाना चाहिए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे दोष मन-मंदिर में प्रभु की उपस्थिति से दूर हो सकते हैं। धर्म की सफलता के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ता आवश्यक है। तप, पूजा और साधना करते-करते जब भीतर प्रसन्नता आने लगे तो उस प्रयास को जारी रखना चाहिए।

धर्मसभा में साध्वीश्री ज्ञानसुरभिनिधिश्री जी ने 30वें उपवास के पचक्खाण ग्रहण किया। संघ अध्यक्ष तेजराज कोठारी व सचिव आकाश जैन ने बताया कि साध्वीश्री के मासक्षमण तप के अनुमोदनार्थ मंगलवार को तप-वंदना एवं सामूहिक सामायिक के कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे।

विद्यालयों का खेल मिलाप 17 को

चेन्नई//दक्षिण भारत। शिक्षा जहाँ मनुष्य के बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करती है, वहीं खेल उसके व्यक्तित्व में अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य, संघर्षशीलता एवं सामूहिक चेतना का संचार करते हैं। इसी भावना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए एसएस जैन एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत संचालित विद्यालयों का संयुक्त क्रीड़ा महोत्सव खेल मिलाप 17 अगस्त को नेहरू इनडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन, विशिष्ट अतिथि के रूप मे शिक्षा मंत्री राजमोहन एवं युवा ओलंपिक 2026 के लिए चयनित शुभ चौधरी उपस्थित होंगे। खेल महोत्सव के चेयरमैन दलजीत सिंह ढढा, वाइस चेयरमैन प्रदीप चोरड़िया, भवनेश देवड़ा एवं समन्वयक डॉ. जयश्री एसएस जैन एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष पदम चंद चोरड़िया, उपाध्यक्ष हस्तीमल चौधरी, महासचिव अभय श्रीश्रीमाल, कैलाश चंद चोरड़िया एवं संयुक्त सचिव महेंद्र सिंह ढढा आयोजन की तैयारियों में लगे हुए है।

अमृतवाणी सत्संग

चेन्नई। यहां परम श्रद्धेय श्री राम जी की कृपा से संत शिरोमणि ब्रह्मलीन श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के एकमेव आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री प्रेम जी महाराज के अनन्य सेवक एवं सदशिष्य श्री ब्रजमोहन जी महाराज, प्रमुख श्री स्वामी सत्यानंद सत्संग भवन (श्री राम शरणम्), कालकाजी, नई दिल्ली के पावन सानिध्य में अमृतवाणी सत्संग बड़े ही श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर मनमोहनजी द्वारा अमृतवाणी पाठ एवं भजन प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात मधु सोनी, ममता शर्मा एवं अशोक जोशी द्वारा भावपूर्ण भजन-कीर्तन प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात पूज्य श्री महाराज जी ने अपने अमृतमयी प्रवचनों द्वारा सभी भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। अंत में भक्तों को पावन नाम दीक्षा प्रदान की गई। अरविंद कुमार शर्मा के निवास स्थान पर आयोजित समारोह मेंअमृतवाणी चेन्नई के सभी भक्तों का भरपूर सहयोग एवं सहभागिता रहा।

अपरम्पार है दान की महिमा : अभिजीतमुनि

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के गणेश बाग स्थानक में चातुर्मासार्थ विराजित अभिजीतमुनिजी ने अपने प्रवचन में कहा कि दान देने की भावना से मन में उदारता का भाव जागृत होता है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों के निवास के लिए करता है अर्थात धर्मशाला, धर्मस्थान, स्कूल, रैन बसेरा, विकलांग आश्रम, गौशाला, चिकित्सालय बनाने में लगाता है उसके धन से पुण्य की प्राप्ति तथा धन की अधिकता होती है। संतश्री ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिएं जिससे आत्मशांति की प्राप्ति हो। दान देने से आत्मसंतोष व शांति की प्राप्ति होती है इसलिए उदारहृदय से दान करना चाहिए। दान की महिमा अपरम्पार है।

मद्रास कांवड़ संघ की कावड़ यात्रा सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के बीच मद्रास कांवड़ संघ, चेन्नई की रजत जयंती वर्ष 2026 की पावन कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सेवा, समर्पण एवं शिवभक्ति के अद्भुत संगम के साथ सम्पन्न हुई। संघ के 85 शिवभक्तों ने सुल्तानगंज के गंगाधाम से पवित्र गंगाजल भरकर कांवड़ उठाई और लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुँचकर भगवान बाबा बैद्यनाथ का विधिवत जलाभिषेक किया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने बाबा वासुकीनाथ धाम में भी दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। मद्रास कांवड़ संघ के लिए यह यात्रा इसलिए भी विशेष रही क्योंकि वर्ष 2026 में संघ ने अपनी कांवड़ यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण किए, जिसके उपलक्ष्य में पूरे आयोजन को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर संघ ने अपनी धार्मिक यात्रा के साथ-साथ सेवा कार्यों को विशेष महत्व देते हुए संपूर्ण कांवड़ मार्ग पर हजारों शिवभक्तों की निःस्वार्थ सेवा का संकल्प पूरा किया।

मद्रास कांवड़ संघ के अध्यक्ष संजय मूंदड़ा ने बताया कि रजत जयंती वर्ष की यात्रा को पूरी तरह सेवा-प्रधान एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए पहले से व्यापक तैयारियाँ की गई थीं।

उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सीमित दूरी की पदयात्रा रखी गई, जिससे श्रद्धालु आराम से यात्रा पूरी कर सकें। प्रत्येक पड़ाव पर उनके लिए भोजन, विश्राम एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ की गईं। कई दिनों की कठिन पदयात्रा, सेवा एवं भक्ति के बाद 8 अगस्त को 85 शिवभक्तों ने बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचकर पवित्र गंगाजल से बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के दौरान सभी श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और भगवान शिव से परिवार, समाज एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की।

सप्ताहिक सुन्दरकांड पाठ के हुए 25 वर्ष पूर्ण

मन्नड़ी सुन्दरकांड समिति द्वारा विशेष सुन्दरकांड पाठ

चेन्नई/दक्षिण भारत।। यहां श्री मन्नडी सुंदरकांड समिति द्वारा पिछले 25 वर्षों से अनवरत साप्ताहिक सुंदरकांड का पाठ विभिन्न भक्तों के घरों हर शनिवार पर किया जाता रहा है।

इसी पावन परम्परा के क्रम में, 25 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में इस बार का साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ का विशेष आयोजन 9 अगस्त को तिरुपति धाम के पास स्थित श्री जपाली हनुमान जी मंदिर में किया गया।

इस विशेष सुंदरकांड पाठ में चेन्नई से पधारे समिति के 35 सदस्यों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। पाठ के उपरांत आरती एवं प्रसाद का आयोजन किया गया। स्थानीय व्यवस्था महावीर सेन ने की। समिति के नारायण तापड़िया ने बताया कि 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष समिति द्वारा साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ, चेन्नई एवं आसपास के विभिन्न मंदिरों में अधिक से अधिक सुंदरकांड पाठ कराने का संकल्प लिया गया है। इस आयोजन में भरत मकवाना, नरेश मकवाना और सतीश जायसवाल का व्यवस्था में विशेष सहयोग रहा।

एकल युवा के रक्तदान शिविर में 254 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी(एकल)युवा द्वारा रविवार

को आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में कुल 254 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। युवा अध्यक्ष प्रितेश बुरड़ ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एकल जेम्स के कमलेश डूंगरवाल, एफटीएस के संरक्षक मुरारीलाल सरावगी, सुरेन्द्र गोयल, रमेश अग्रवाला, एफटीएस साउथ जोन सचिव बिमल सरावगी, चैप्टर के अध्यक्ष हाथीमल बैद एवं महिला समिति अध्यक्ष कांता काबरा सहित अनेक अतिथियों ने शिविर का शुभारंभ किया। इस आयोजन में 10 विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं तथा समाजों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। युवा सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि शिविर की सफलता में चारों संयोजकों आयुष अग्रवाला, शुभम लोहिया, प्रवीण गहलोत एवं अरुण शर्मा का विशेष योगदान रहा। शिविर में सभी रक्तदाताओं को संस्था की ओर से उपहार दिए गए तथा विक्रम अग्रवाल परिवार के सौजन्य से 25 आकर्षक लकी ड्रॉ पुरस्कार भी निकाले गए। युवा मेंटर आशीष गुप्ता ने 254 यूनिट रक्त संग्रह को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस अवसर पर संस्था के अनेक सदस्यों ने सहयोग दिया।

इच्छाओं के साथ संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों को भी सहेजना जरूरी : साध्वी प्रियरंजनाश्री

चेन्नई/दक्षिण भारत। यहां रिथर्डन रोड़ स्थित कुशल बाग में चातुर्मासार्थ विराजित साध्वीश्री प्रियरंजनाश्रीजी ने प्रवचन में नारी जीवन, संस्कार, मर्यादा और वैवाहिक जीवन में आपसी सम्मान के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, लेकिन संस्कार और मर्यादा कभी पुराने नहीं होते।

साध्वीश्री ने कहा कि आज के बदलते दौर में इच्छाएं और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। आज अनेक युवा अपने जीवनसाथी को लेकर कहते हैं कि उन्हें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, इतनी सुविधाएं चाहिए और जीवन बिल्कुल अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन केवल सुविधाएं और इच्छाएं जीवन को सुखी नहीं बनातीं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए संस्कार, समझ, समर्पण और मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि परिवार केवल साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि एक-दूसरे के सम्मान, विश्वास और भावनाओं को समझने से बनता है। यदि किसी बात पर मतभेद हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर विचार करना चाहिए। अपने मान-सम्मान की रक्षा के साथ सामने वाले के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से युवतियों और युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आधुनिकता को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर संस्कारों और मर्यादाओं को छोड़ देना उचित नहीं। सच्ची आधुनिकता वही है, जिसमें शिक्षा और स्वतंत्र सोच के साथ संस्कार, विवेक और जिम्मेदारी भी बनी रहे। यह जानकारी संघ के पदम टाटिया ने दी है ।

नम्रता से खुलता है गुणों का द्वार : मुनि तीर्थचैतन्य

चेन्नई। यहां किलपॉक स्थित एससी शाह भवन में चातुर्मासार्थ विराजित मुनिश्री तीर्थचैतन्य विजयजी म. ने प्रवचन में कि आचारांग सूत्र की शुरुआत ही देव, गुरु और धर्म को नमस्कार से होती है। यह नमस्कार केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन की पहली आवश्यकता है। देव वह हैं जो हमें देते हैं, गुरु वह हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और धर्म वह है जो हमें उस सत्य का अनुभव कराता है। उन्होंने कहा कि जीवन में ज्ञान, गुण और संस्कार तभी उतरते हैं, जब हृदय में नम्रता आती है। व्यक्ति कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितने ही प्रवचन सुन ले, लेकिन यदि भीतर विनम्रता नहीं है तो ज्ञान कानों तक ही सीमित रह जाता है, हृदय तक नहीं पहुंचता। भगवान की वाणी को भी केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे श्रद्धा और दृढ़ता के साथ आत्मसात करना आवश्यक है, ताकि वह भव-भव में आत्मकल्याण का कारण बने। उन्होंने स्मरण-भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान का दृढ़ स्मरण व्यक्ति को अधोगति से उठाकर आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाने की शक्ति रखता है। गहरी श्रद्धा और स्मरण इतना प्रगाढ़ हो जाए कि एक छोटे से पत्थर के टुकड़े में भी अपने आराध्य का साक्षात्कार हो जाए। मोक्षमार्ग को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुनिश्री ने कहा कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन यह पता नहीं कि शुरुआत कहां से करनी है। उन्होंने कहा कि आत्मा के स्वरूप को समझ लेना ही अनंत जन्म-मरण के चक्र को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। उन्होंने कहा कि अपने भीतर दोषों का अनुभव होना भी साधना की प्रगति का संकेत है। गुरु के बताए मार्ग की ओर बढ़ना अभिमुखता है, जबकि उसके विपरीत दिशा में जाना विमुखता है। इसलिए जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति नम्रता, श्रद्धा, स्मरण और सन्मुखता को अपनाकर ज्ञान को केवल सुनना नहीं, बल्कि आत्मस्थ करना ही सच्ची साधना है।

सर्वसमाज कांवड़ यात्रा सम्पन्न

तिरुपुर/दक्षिण भारत। यहां 8 अगस्त को भवानी कावेरी नदी से शाम को पूजा अर्चना के उपरांत सर्वसमाज शिव कांवड़ संघ के सानिध्य में 56 कांवड़िए जल लेकर 70 किलोमीटर दूर अविनाशी शंकर भोलेनाथ के मंदिर के लिए 'बोल बम' के जयकारों के साथ निकल पड़े हैं।

कांवड़ संघ के मुख्य भागीरथ गुलेरिया, अरुण पारीक, डुंगर सिंह, अशोक राव, कैलाश पारीक ने बताया कि इस 70 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा सोमवार को सुबह अविनाशी शंकर मन्दिर पहुंचेगी और यहां पूजा अर्चना के बाद भोले बाबा पर जलाभिषेक किया जाएगा।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityat at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.